कानपुर, शनिवार, 7 फरवरी, 2026
वर्षः 03, अंकः 38, पृष्ठः 8+4

सच्चाई के दम पर
जोश के साथ...

swarajindia2023@gmail.com swarajindianews swarajindianews

ई-पेपर पढ़ने के लिए क्लिक करें
https://epaper.swarajindianews.com
Website: www.swarajindianews.com

स्वराज इंडिया

सांध्यकालीन समाचार पत्र

इनसाइड ईरान पर अमेरिका का नया प्रतिबंध प्रहार...>Pg12

सुतरखाना-सेंट्रल स्टेशन मार्ग बंद ...>Pg03

मूल्य: 2 ₹

35-40 मिनट में सिमटेगा दो शहरों का सफर

1 अप्रैल से खुलेगा लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेस-वे

खबरः एक नजर में

- 1 अप्रैल से लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे जनता के लिए खुलेगा
- मुख्य निर्माण कार्य पूरा, फिनिशिंग व तकनीकी जांच अंतिम चरण में
- 2-3 घंटे का सफर घटकर 35-40 मिनट में
- यात्रा समय में करीब 60% तक बचत
- एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 62.7 किलोमीटर
- परियोजना लागत लगभग 4,700 करोड़ रुपये
- फिलहाल 6 लेन, भविष्य में 8 लेन तक विस्तार संभव
- अधिकतम स्पीड लिमिट 120 किमी प्रति घंटा
- 4 बड़े पुल, 25 छोटे पुल और 4 फ्लाईओवर
- पैदल यात्रियों के लिए 11, हल्के वाहनों के लिए 13 अंडरपास
- पूरे रूट पर सीसीटीवी निगरानी और कंट्रोल रूम
- हादसे की स्थिति में 15 मिनट में राहत पहुंचाने की व्यवस्था
- व्यापार, उद्योग और परिवहन को मिलेगी नई रफ्तार

प्रमुख संवाददाता, स्वराज इंडिया

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के दो प्रमुख औद्योगिक और प्रशासनिक शहरों लखनऊ और कानपुर के बीच आवागमन करने वालों के लिए बड़ी सौगात तैयार है। लंबे इंतजार और कई चरणों में चले निर्माण कार्य के बाद लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे को 1 अप्रैल से आम जनता के लिए खोलने की तैयारी पूरी कर ली गई है। एक्सप्रेसवे का मुख्य निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, जबकि कुछ स्थानों पर अंतिम फिनिशिंग, साइन बोर्ड और तकनीकी जांच का काम जारी है।

एक्सप्रेसवे के चालू होते ही जहां अभी लखनऊ से कानपुर पहुंचने में दो से तीन घंटे तक का समय लग जाता है, वहीं अब यह दूरी महज 35 से 40 मिनट में पूरी हो सकेगी। इससे न केवल आम यात्रियों को राहत मिलेगी, बल्कि रोजाना सफर करने वाले नौकरीपेशा लोगों, कारोबारियों और परिवहन से जुड़े लोगों के समय और ईंधन की भी बड़ी बचत होगी। अनुमान है कि यात्रा समय में करीब 60 प्रतिशत तक की कमी आएगी।

करीब 62.7 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे को आधुनिक मानकों के अनुसार छह लेन में तैयार किया गया है। भविष्य में यातायात के बढ़ते दबाव को देखते हुए इसे आठ लेन तक विस्तारित करने की भी योजना है। एक्सप्रेसवे पर वाहनों की अधिकतम गति सीमा 120 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है, जिससे नियंत्रित और सुरक्षित हाई-स्पीड सफर संभव हो सकेगा।

एक्सप्रेसवे का मुख्य निर्माण कार्य पूरा , कुछ स्थानों पर फिनिशिंग, साइन बोर्ड और तकनीकी जांच का काम चल रहा

इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर करीब 4,700 करोड़ रुपये की लागत आई है। एक्सप्रेसवे को मजबूत और टिकाऊ बनाने के लिए इसमें चार बड़े पुल, 25 छोटे पुल, चार फ्लाईओवर बनाए गए हैं। साथ ही स्थानीय आवागमन को प्रभावित न करने के उद्देश्य से पैदल यात्रियों के लिए 11 अंडरपास और हल्के वाहनों के लिए 13 अंडरपास का निर्माण किया गया है, ताकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों का संपर्क बना रहे।

सुरक्षा के लिहाज से पूरे एक्सप्रेसवे पर विशेष ध्यान दिया गया है। सीसीटीवी कैमरों से पूरे रूट की निगरानी की जाएगी। किसी भी दुर्घटना या आपात स्थिति में 15 मिनट के भीतर एंबुलेंस और राहत टीम मौके पर पहुंच सके, इसके लिए कंट्रोल रूम और रेस्क्यू सिस्टम को सक्रिय किया गया है। इसके अलावा जगह-जगह संकेतक, रिफ्लेक्टर और सड़क सुरक्षा से जुड़े उपकरण लगाए गए हैं।

लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे के शुरू होने से क्षेत्रीय विकास को भी बड़ा बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इससे उद्योग, व्यापार, लॉजिस्टिक्स, रियल एस्टेट और पर्यटन को गति मिलेगी।

दोनों शहरों के बीच तेज और सुगम संपर्क स्थापित होने से राजधानी लखनऊ और औद्योगिक नगरी कानपुर के बीच आर्थिक गतिविधियां और मजबूत होंगी। यह एक्सप्रेसवे प्रदेश सरकार की आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर नीति का एक अहम हिस्सा माना जा रहा है और आने वाले समय में यह पूर्वांचल, बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश की ओर जाने वाले यातायात के लिए भी एक प्रभावी कड़ी साबित हो सकता है।

सेठ आनंदराम जयपुरिया स्कूल का 42वाँ वार्षिक खेल दिवस भव्यता के साथ संपन्न

» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। सेठ आनंदराम जैपूरिया स्कूल, कानपुर का 42वाँ वार्षिक खेल दिवस विद्यालय प्रांगण में अत्यंत भव्यता, अनुशासन और उत्साहपूर्ण वातावरण में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस गौरवशाली आयोजन में सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता निभाते हुए खेल भावना, सहयोग, नेतृत्व तथा सर्वांगीण विकास के आदर्शों को साकार रूप में प्रस्तुत किया। संपूर्ण परिसर उमंग, अनुशासन और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की ऊर्जा से आलोकित रहा।कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित कैप्टन सतीश कुमार रहे। कैप्टन सतीश कुमार भारत के प्रथम मुक्केबाज हैं जिन्होंने सुपर हेवीवेट वर्ग में देश का प्रतिनिधित्व किया। उनकी सौम्य उपस्थिति और प्रेरक खेल यात्रा ने विद्यार्थियों को दृढ़ संकल्प, समर्पण और उत्कृष्ट जीवन कौशल का संदेश दिया।

कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि के आत्मीय स्वागत के साथ हुआ। इसके पश्चात मनमोहक तीरंदाजी प्रदर्शन ने दर्शकों को सटीकता, एकाग्रता और आत्मनियंत्रण का सजीव अनुभव कराया। तत्पश्चात मुख्य अतिथि ने प्रधानाचार्य गणेश प्रसाद तिवारी एवं विद्यालय नेतृत्व दल के साथ विद्यालय ध्वज फहराया। प्रेरणास्पद संगीत की गूंज और अनुशासित कदमताल ने विद्यार्थियों के कठोर प्रशिक्षण, सामूहिक समन्वय और एकता की भावना को प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त किया। इसके उपरांत मुख्य अतिथि द्वारा खेल प्रतियोगिताओं की औपचारिक उद्घोषणा के साथ खेल दिवस का विधिवत शुभारंभ हुआ।

कार्यक्रम का अत्यंत प्रेरणादायी क्षण खेल मशाल प्रज्वलन रहा, जिसका नेतृत्व विद्यालय के स्पोर्ट्स कैप्टन अस्सलान इमरान ने किया, जो सीआईएससीई नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 के स्वर्ण पदक विजेता हैं। मशाल रिले में राष्ट्रीय स्तर की विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट उपलब्धियाँ प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की सहभागिता ने इस क्षण को और भी गौरवमयी बना दिया।

इस अवसर पर आयोजित ट्रैक एवं फील्ड प्रतियोगिताओं—50 मीटर, 80 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर दौड़,

बाधा दौड़, रिले एवं ऊँची कूद—में विद्यार्थियों ने अद्भुत ऊर्जा और खेल कौशल का प्रदर्शन किया। साथ ही पंच-तत्व नृत्य, योग ड्रिल, क्लैप ड्रिल, फ्लैग ड्रिल, एरोबिक ड्रिल, बॉल ड्रिल तथा शक्तिशाली कराटे प्रदर्शन ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया और शारीरिक-मानसिक संतुलन का सुंदर संदेश दिया।

विद्यालय ने खेल उपलब्धियों के साथ-साथ शैक्षणिक उत्कृष्टता का भी उत्सव मनाया। सीआईएससीई कक्षा 1 से 9 एवं कक्षा 11 के विद्यार्थियों को शैक्षणिक पुरस्कार प्रदान किए गए, जिससे विद्यालय की शैक्षणिक तथा पाठ्यक्रम-सहगामी गतिविधियों में उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता और सुदृढ़ हुई।इस अवसर पर विद्यालय के पूर्व छात्रों की सहभागिता भी विशेष आकर्षण का केंद्र रही। 'पूर्व छात्र कार्यक्रम' में दौड़ एवं रस्साकशी जैसी प्रतियोगिताओं ने समारोह में उत्साह और अपनत्व का अनूठा रंग भर दिया।

कार्यक्रम का समापन प्रमुख एथलेटिक स्पर्धाओं एवं ओवरऑल ट्रॉफी के पुरस्कार वितरण के साथ हुआ। मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में विद्यार्थियों को लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अडिग रहने और निरंतर परिश्रम करने का संदेश दिया। अंत में उप-प्रधानाचार्य महेश मिश्रा द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद ज्ञापन ने आयोजन को गरिमामय पूर्णता प्रदान की। इस अवसर पर विद्यालय की उप-प्रधानाचार्या मधुश्री भौमिक, जीएम शैलेंद्र अग्निहोत्री, मुख्य अध्यापिका सीनियर स्कूल ममता शर्मा, मुख्य अध्यापिका जूनियर स्कूल शालिनी शुक्ला, कैम्ब्रिज स्कूल की मुख्य अध्यापिका अपर्णा चौहान, अभिभावकगण, शिक्षकवृंद एवं विद्यार्थीगण उपस्थित रहे। राष्ट्रगान के साथ यह प्रेरणास्पद और अत्यंत सफल खेल दिवस संपन्न हुआ।

हास्य कलाकार राजीव निगम का शो 'बहुत हुआ सम्मान' कल

» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। देश के जाने-माने हास्य एवं व्यंग्य कलाकार राजीव निगम का चर्चित शो 'बहुत हुआ सम्मान' आगामी 8 फरवरी (रविवार) को मर्चेन्ट चैम्बर हॉल में आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम सायं 6 बजे से प्रारंभ होगा। कानपुर में इस तरह का आयोजन पहली बार हो रहा है, जिसे लेकर दर्शकों में खासा उत्साह देखा जा रहा है।

राजीव निगम देश के विभिन्न शहरों में अपने कार्यक्रमों के माध्यम से श्रोताओं को न केवल गुदगुदाते रहे हैं, बल्कि उन्हें सोचने पर भी मजबूर किया है। उन्होंने बताया कि 'बहुत हुआ सम्मान' केवल हास्य-व्यंग्य का शो नहीं, बल्कि राजनीति, समाज और देश के मौजूदा हालात को आईना दिखाने का माध्यम है।

उल्लेखनीय है कि राजीव निगम टेलीविजन के कई बड़े और लोकप्रिय कार्यक्रमों का हिस्सा रह चुके हैं। वे कपिल

शर्मा शो, कॉमेडी सर्कस, लाफ्टर चैलेंज जैसे चर्चित शो में अपनी लेखनी और अभिनय से अलग पहचान बना चुके हैं। टेलीविजन के जरिए उन्होंने घर-घर में अपनी पहचान स्थापित की, वहीं लाइव स्टेज शोज़ के माध्यम से देशभर में दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया।

डिजिटल प्लेटफॉर्म के आगमन के साथ राजीव निगम ने सोशल मीडिया और ऑनलाइन वीडियो के जरिए भी अपनी बात लोगों तक पहुंचाई। आज जब कॉमेडी तेजी से डिजिटल होती जा रही है, उन्होंने इस बदलाव को अपनाते हुए अपनी प्रासंगिकता बनाए रखी है।

राजीव निगम की कॉमेडी केवल हंसी तक सीमित नहीं रहती। उनके व्यंग्य में छुपा कटु सत्य हास्य की चाशनी में लिपटा होता है, जो हर उम्र और हर वर्ग के दर्शकों को प्रभावित करता है। उन्होंने यह सिद्ध किया है कि स्टैंड-अप कॉमेडी सिर्फ हल्का-फुल्का मनोरंजन नहीं, बल्कि सामाजिक संवाद का एक सशक्त माध्यम भी हो सकती है। हिंदी स्टैंड-अप कॉमेडी को लोकप्रिय बनाने में उनका योगदान उल्लेखनीय रहा है।

कानपुर से मुंबई तक का उनका सफर संघर्ष, अनुभव और सफलता की प्रेरक कहानी है। आज के दौर में, जब हास्य के नाम पर सतही मनोरंजन परोसा जा रहा है, राजीव निगम जैसे कलाकार सच्ची और

चीनी मांझा को लेकर पतंग दुकानों में छापा

» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर।गंगाघाट पुलिस ने शुक्लागंज के विभिन्न क्षेत्रों में पतंग की दुकानों पर छापेमारी कर चीनी मांझा न बेचने की सख्त चेतावनी दी है। पुलिस ने साफ किया है कि इस प्रतिबंधित मांझे की बिक्री करने वालों के खिलाफ हत्या जैसी गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की जाएगी।

शुक्लागंज में चीनी मांझा की बिक्री पर रोक लगाने के लिए गंगाघाट कोतवाली पुलिस ने शुक्रवार को नगर की कई पतंग की दुकानों पर छापा मारा। दुकानदारों को चीनी मांझा बिक्री न करने की हिदायत दी। साथ ही बिक्री करने पर गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज करने की बात कही। मालूम हो कि चीनी मांझा से आए दिन हादसे हो रहे हैं। इसको देखते हुए सरकार ने इसकी ब्रिकी पर रोक लगाते हुए इसे बेचने-खरीदने और घटना करने करने वालों के खिलाफ हत्या समेत गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए है।

इसको लेकर शुक्रवार को गंगाघाट कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अजय कुमार सिंह ने फोर्स के साथ मनोहर नगर, डाकतार कॉलोनी, शक्ति नगर, गांधी नगर समेत आधा दर्जन से अधिक पतंग की दुकानों में छापा मारा।

कोतवाली प्रभारी ने बताया कि पतंग दुकानदारों को हिदायत दी गई है कि किसी भी हाल में चीनी मांझा की बिक्री न करें। वहीं, छापे की इस कार्रवाई से पतंग दुकानदारों में हड़कंप मचा रहा।

सुतरखाना-सेंट्रल स्टेशन मार्ग बंद

यात्रियों की मुश्किलें दोगुनी

आधा किलोमीटर घूमकर प्लेटफार्म नंबर 9 तक पहुंचने को मजबूर यात्री

- सुतरखाना से कानपुर सेंट्रल स्टेशन का सीधा प्रवेश मार्ग अचानक बंद
- प्लेटफार्म नंबर 9 तक पहुंचने के लिए यात्रियों को करीब आधा किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही
- आरपीएफ की तैनाती के साथ बैरिकेडिंग, बंद रास्ते से प्रवेश पूरी तरह रोका गया
- मेट्रो निर्माण और रेलवे सुंदरीकरण कार्य के बीच बढ़ी यात्रियों की परेशानी
- घंटाघर चौराहे के जाम से बचने का प्रमुख विकल्प था सुतरखाना मार्ग
- बुजुर्गों, महिलाओं और भारी सामान वाले यात्रियों को सबसे ज्यादा दिक्कत
- बाहर से आने वाले यात्रियों को वैकल्पिक रास्तों की जानकारी न होने से भ्रम
- स्थानीय दुकानदारों और ऑटो चालकों की रोज़ी-रोटी पर पड़ा असर
- बिना पूर्व सूचना मार्ग बंद किए जाने से यात्रियों में नाराजगी
- निर्माण अवधि तक वैकल्पिक व सुगम मार्ग की मांग तेज

स्वराज इंडिया न्यूज

कानपुर। शहर के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कानपुर सेंट्रल तक पहुंचने वाला सुतरखाना मार्ग अचानक बंद कर दिए जाने से यात्रियों की परेशानी काफी बढ़ गई है। इस मार्ग के बंद होने के बाद यात्रियों को अब पार्सल घर की ओर से करीब आधा किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर लगाकर स्टेशन और खासतौर पर प्लेटफार्म नंबर 9 तक पहुंचना पड़ रहा है।

पहले से ही मेट्रो निर्माण और रेलवे के सुंदरीकरण कार्यों के चलते यात्री अव्यवस्था झेल रहे थे। ऐसे में सुतरखाना जैसे सबसे सुगम और व्यस्त प्रवेश मार्ग के बंद होने से स्थिति और गंभीर हो गई है। बाहर से आने वाले यात्रियों, बुजुर्गों, महिलाओं और भारी सामान के साथ सफर करने वालों को सबसे

अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मार्ग बंद होने के बाद मौके पर आरपीएफ के जवान तैनात कर बैरिकेडिंग कर दी गई है, ताकि कोई भी यात्री बंद रास्ते से स्टेशन में प्रवेश न कर सके। हालांकि, अचानक किए गए इस बदलाव की पूर्व सूचना न होने से यात्रियों में नाराजगी देखी जा रही है।

घंटाघर चौराहे पर लगने वाले जाम और भीड़ से बचने के लिए रोज़ हजारों यात्री सुतरखाना मार्ग का इस्तेमाल करते थे। यह रास्ता स्टेशन तक पहुंचने का सबसे आसान और तेज़ विकल्प माना जाता था। अब इसके बंद होने से न केवल यात्रियों की परेशानी बढ़ी है, बल्कि स्थानीय दुकानदारों और बड़ी संख्या में ऑटो चालकों की आजीविका भी प्रभावित होने लगी है।

यात्रियों का कहना है कि जब तक निर्माण कार्य जारी है, तब तक वैकल्पिक और सुचारु मार्ग की व्यवस्था की जानी चाहिए। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि रेलवे और प्रशासन यात्रियों को हो रही इस असुविधा का समाधान कब और कैसे करेगा।

फर्जी जज बन ठगी करने वाले वकील की जमानत अर्जी खारिज

प्रमुख संवाददाता, स्वराज इंडिया

- अपर जिला जज सप्तम की कोर्ट ने जमानत ठुकराई, कहा—आरोप गंभीर, रिहाई से जांच प्रभावित होगी
- बार एसोसिएशन ने निकाला बाहर, बार काउंसिल पहले ही कर चुकी है एक साल के लिए डिबार

कानपुर। खुद को न्यायिक अधिकारी बताकर लोगों से ठगी करने के आरोपी अधिवक्ता विष्णु शंकर गुप्ता को अदालत से कोई राहत नहीं मिली। अपर जिला जज सप्तम आज़ाद सिंह की अदालत ने उसकी जमानत अर्जी सिरे से खारिज कर दी। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि आरोप बेहद गंभीर हैं और उपलब्ध साक्ष्य आरोपी के खिलाफ जाते हैं, ऐसे में जमानत देना न्यायहित में नहीं होगा।

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विनोद त्रिपाठी ने अदालत को बताया कि आरोपी पेशे से वकील होते हुए भी खुद को जज बताकर फरियादियों को गुमराह करता रहा। न्यायिक प्रभाव का झांसा देकर उसने मुकदमों में फायदा दिलाने के नाम पर मोटी रकम वसूली।

मामले के सामने आने के बाद अधिवक्ता समुदाय ने भी सख्त रुख अपनाया। बार एसोसिएशन ने आरोपी की सदस्यता तत्काल समाप्त कर दी, जबकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया (नई दिल्ली) ने पेशेवर आचरण के गंभीर उल्लंघन को मानते हुए उसे एक वर्ष के लिए डिबार कर दिया।

अभियोजन ने दलील दी कि आरोपी के

खिलाफ कई शिकायतें और तथ्य रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। जमानत मिलने की स्थिति में वह गवाहों और साक्ष्यों को प्रभावित कर सकता है। अदालत ने इन दलीलों को स्वीकार करते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी। फिलहाल मामले की विवेचना जारी है और आरोपी न्यायिक हिरासत में रहेगा।

शराबी पिता बना जल्लाद, एक साल की बेटी को ठंडे पानी में डुबोया, तड़प-तड़प कर मौत

प्रमुख संवाददाता, स्वराज इंडिया

- मासूम एक महीने तक अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझती रही

कानपुर। रावतपुर इलाके में इंसानियत को झकझोर देने वाली घटना ने पूरे शहर को सन्न कर दिया। नशे में धुत एक पति ने पहले पत्नी को बेरहमी से पीटा, फिर अपनी ही एक साल की मासूम बेटी को ठंडे पानी से भरे टब में डालकर मौत के हवाले कर दिया। मासूम एक महीने तक अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझती रही, लेकिन आखिरकार शनिवार को उसने दम तोड़ दिया। बच्ची की मौत के बाद गुस्साए मायके पक्ष के लोग शव लेकर ससुराल पहुंचे और खुलेआम हत्या का आरोप लगाते हुए सड़क पर हंगामा किया।

बताया गया कि आरोपी पति गोपाल गुप्ता नशे का आदी है और शादी के बाद से ही उसकी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही थी। शिकायतें हुईं, परिवार को बताया गया, लेकिन न समाज जागा, न सिस्टम हरकत में आया—नतीजा यह कि एक मासूम की जान चली गई।

नवाबगंज थाना क्षेत्र के सूर्य बिहार निवासी राम सिंह की बेटी रुचि का प्रेम विवाह 16 सितंबर 2024 को रावतपुर निवासी ई-रिक्शा चालक गोपाल गुप्ता से हुआ था। शादी के कुछ ही दिनों बाद गोपाल की शराबखोरी और दरिंदगी सामने आ गई। आए दिन पत्नी के साथ मारपीट होती रही। जब ससुराल वालों

से गुहार लगाई गई तो उन्होंने "अलग रहो" कहकर हाथ झाड़ लिए।

इसके बाद पति-पत्नी किराये के कमरे में रहने लगे, लेकिन वहां भी शराबी पति की क्रूरता और बढ़ गई। करीब एक महीने पहले गोपाल ने नशे में धुत होकर पत्नी को पीटा और फिर गुस्से में मासूम बच्ची को उठाकर ठंडे पानी से भरे टब में डाल दिया। चीख-पुकार के बीच किसी तरह बच्ची को बाहर निकाला गया और अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद मां बच्ची को लेकर मायके चली गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ठंड और सदमे से बच्ची की हालत लगातार बिगड़ती चली गई। गुरुवार को उसकी हालत फिर नाजुक हुई और शुक्रवार को इलाज के दौरान मासूम की मौत हो गई।

मासूम की मौत की खबर मिलते ही मायके पक्ष का गुस्सा फूट पड़ा। शव लेकर ससुराल पहुंचे परिजनों ने बेटी की हत्या का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। हालात बिगड़ते देख रुचि ने 112 नंबर डायल किया। सूचना मिलते ही रावतपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में लिया।

पुलिस ने मासूम के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम में विसरा सुरक्षित रखा गया है, जिससे मौत के असली कारणों का पता लगाया जा सके। डीसीपी पश्चिम कासिम आबिदी ने बताया कि पति-पत्नी के बीच विवाद के दौरान आरोपी पति ने नशे की हालत में बच्ची को पानी के टब में डाल दिया था, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। फिलहाल परिवार की ओर से तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलते ही आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बड़ा सवाल है कि जब एक मां महीनों से हिंसा की शिकार थी, जब एक मासूम अस्पताल में तड़प रही थी तब सिस्टम कहां था? और क्या अब भी आरोपी को कानून की पकड़ में लाने में देर की जाएगी?

स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 की तैयारी 'टोकोगे तो रोकोगे' अभियान लॉन्च

स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान में जनभागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जुटा नगर निगम

» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 की तैयारियों को लेकर नगर निगम ने कमर कस ली है। इसी क्रम में नगर निगम मुख्यालय स्थित सभागार में नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय की अध्यक्षता में अधिकारियों की बैठक व कार्यशाला आयोजित की गई। बैठक में स्वच्छ सर्वेक्षण में शहर की रैंकिंग बेहतर करने को लेकर विस्तृत चर्चा की गई।

कार्यशाला में अपर नगर आयुक्त प्रथम, अपर नगर आयुक्त द्वितीय, मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी, समस्त नगर स्वास्थ्य अधिकारी, मुख्य अभियन्ता सिविल, सभी जोनल अभियन्ता, जोनल अधिकारी, जोनल स्वच्छता अधिकारी तथा एसबीएम एडवाइजरी टीम के विशेषज्ञ उपस्थित रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य पिछले वर्ष के स्वच्छ सर्वेक्षण में संकेतकवार प्राप्त अंकों की समीक्षा करना और जिन बिंदुओं पर अपेक्षा से कम अंक मिले, वहां सुधार की कार्ययोजना तैयार करना रहा।

नगर आयुक्त ने शहर के सौन्दर्यीकरण और साफ-सफाई पर विशेष जोर देते हुए सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालयों को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। साथ ही शहर में येलो स्पॉट कम करने के लिए स्मार्ट सिटी द्वारा बनाए गए मूत्रालयों को सही स्थिति में रखने के निर्देश दिए गए। डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन और स्रोत पर ही कचरे के पृथक्करण को और बेहतर बनाने पर भी चर्चा हुई।

जन-जागरूकता बढ़ाने के लिए 'टोकोगे तो रोकोगे' अभियान चलाने के निर्देश दिए गए, ताकि नागरिक स्वच्छता को लेकर सक्रिय भूमिका निभाएं।

स्वच्छ सर्वेक्षण के संकेतकवार बिंदुओं का प्रस्तुतीकरण नगर स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा किया गया।

नगर आयुक्त ने स्पष्ट किया कि स्वच्छता को लेकर किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में जिम्मेदारी के साथ कार्य करते हुए शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण में बेहतर स्थान दिलाने के लिए प्रयास करें।

नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अमित सिंह गौर ने बताया कि स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान में लगातार कानपुर शहर प्रगति कर रहा है , हम आगे के सर्वेक्षण में भी बेहतर प्रदर्शन करेंगे.

आईजीआरएस में झूठी रिपोर्ट भेजी, आउटसोर्स जेई बर्खास्त

» लापरवाही पर नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय की सख्त कार्रवाई

» खराब स्ट्रीट लाइट सही करने की बजाय शिकायत कर्ता से की अभद्रता

» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। जनमानस की समस्याओं के निस्तारण में लापरवाही बरतना नगर निगम के आउट सोर्सिंग जेई को भारी पड़ा है। नगर आयुक्त ने स्ट्रीट लाइट शिकायत के गलत निस्तारण और अभद्र व्यवहार के मामले में कड़ा कदम उठाते हुए आउटसोर्स अवर अभियन्ता को तत्काल सेवा से पृथक करने के निर्देश दिए हैं, वहीं प्रभारी अधिकारी मार्ग प्रकाश को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

मामला कर्रही क्षेत्र का है, जहां निवासी रोहित कोच्चर ने घर के सामने लगी स्ट्रीट लाइट के लंबे समय से बंद होने की शिकायत दर्ज कराई थी।

नगर आयुक्त के निर्देश पर मार्गप्रकाश विभाग को शिकायत के त्वरित निस्तारण के आदेश दिए गए थे।

जांच में सामने आया कि संबंधित अवर अभियन्ता ने खराब स्ट्रीट लाइट की मरम्मत कराए बिना, प्रकाशित अवस्था वाली अन्य लाइटों के फोटो भेजकर प्रकरण का निस्तारण दर्शा दिया। इससे समस्या यथावत बनी रही।

शिकायतकर्ता ने 31.01.2026 को जनसुनवाई पोर्टल के माध्यम से आईजीआरएस संदर्भ भी प्रस्तुत किया। 06.02.2026 को नगर आयुक्त द्वारा स्वयं शिकायतकर्ता से वार्ता की गई, जिसमें यह स्पष्ट हुआ कि न केवल समस्या का समाधान नहीं हुआ, बल्कि दोबारा संपर्क करने पर अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया गया।

नगर आयुक्त ने इस कृत्य को अनुशासनहीनता, कार्य में लापरवाही और उच्चाधिकारियों के निर्देशों का उल्लंघन मानते हुए गंभीरता से लिया। आदेश के अनुसार आउटसोर्स अवर अभियन्ता को तत्काल सेवा से पृथक करने के निर्देश सेवा प्रदाता को दिए गए हैं। साथ ही शिथिल पर्यवेक्षण के लिए मार्गप्रकाश के प्रभारी अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।नगर आयुक्त ने स्पष्ट किया कि जनमानस की समस्याओं के निस्तारण में किसी भी प्रकार की शिथिलता क्षम्य नहीं होगी। सभी अधिकारी गुणवत्तापरक समाधान सुनिश्चित करें और निस्तारण के बाद शिकायतकर्ता से संतुष्टि प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होगा।

एनजीटी के निर्देश पर गोविंदनगर में सीवर लाइन डालने का रास्ता साफ

स्थानीय दुकानदारों को मिलेगी राहत

» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर । दक्षिण शहर के गोविंदनगर क्षेत्र में गुलाबराज से चावला चौराहे तक प्रस्तावित सीवर लाइन डालने को लेकर चल रहा विवाद अब समाप्त हो गया है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने इस मामले में अहम निर्देश देते हुए बिना किसी देरी के सीवर लाइन डालने का आदेश दिया है।

एनजीटी ने नगर निगम कानपुर को यह भी स्पष्ट निर्देश दिया है कि सीवर कार्य में बाधा डालने वालों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाए, ताकि जनहित का यह महत्वपूर्ण कार्य समय से पूरा हो सके।

गोविंदनगर इलाके में पुरानी और चोक सीवर लाइन के कारण हर बारिश में स्थिति विकराल हो जाती है। जलभराव और गंदगी से स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी समस्या के स्थायी समाधान के लिए लगभग एक करोड़ रुपये की लागत से नई सीवर लाइन स्वीकृत की गई थी। अक्टूबर माह में इसके लिए टेंडर भी जारी कर दिए गए थे।

हालांकि, कुछ व्यापारियों ने खुदाई से व्यापार प्रभावित होने की आशंका जताते हुए कार्य रुकवा दिया था। इस पर क्षेत्रीय पार्षद नवीन पंडित ने एनजीटी में वाद दाखिल किया। सुनवाई के बाद एनजीटी ने सीवर लाइन डालने के पक्ष में फैसला सुनाया।

पार्षद नवीन पंडित के अनुसार, एनजीटी के आदेश के बाद अब बहुत जल्द सीवर लाइन के लिए खुदाई का कार्य शुरू कराया जाएगा। इससे गोविंदनगर क्षेत्र के लोगों को लंबे समय से चली आ रही सीवर समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है।

सम्पादकीय

गुमशुदाओं की तलाश और मिलने की आस

पिछले दिनों इस खबर ने दिल्ली और देश के लोगों को चौंकाया कि इस साल जनवरी माह में ही देश की राजधानी में 800 लोग लापता पाए गए, जिसमें महिला, बच्चे व अन्य वयस्क भी शामिल हैं। जैसा कि स्वाभाविक था दिल्ली में लापता लोगों का आंकड़ा सामने आने के बाद आम लोगों में चिंता व्याप्त हो गई। प्रशासनिक स्तर पर भी इस समस्या की ओर अधिकारियों का ध्यान गया। बेलगाम सोशल मीडिया पर तो इन आंकड़ों पर अपनी-अपनी सुविधा और राजनीतिक हितों के मद्देनजर व्याख्या और बयानबाजी सामने आने लगी। पब्लिक फोरम पर कहा जाने लगा कि यह दिल्ली की कानून व्यवस्था पर प्रश्नचिन्ह है। इन आंकड़ों के सामने आने के बाद घर से निकलने के बाद सुरक्षा इंतजामों को लेकर तमाम तरह की सलाहें दी जाने लगीं। कुछ लोग देश के सिस्टम पर सवाल खड़े करने लगे। कुछ लोगों में भय से जुड़ी प्रतिक्रिया भी सामने आई। लेकिन इस बाबत दिल्ली पुलिस द्वारा जारी आंकड़े भी अधिक चिंता बढ़ाने वाले नजर आए। प्रथम दृष्टया यह खबर परेशान करने वाली है, लेकिन पड़ताल में पाया गया कि यह स्थिति पिछले कुछ सालों के आंकड़ों के ही अनुरूप है। अगर हम पिछले कुछ सालों के आंकड़ों पर नजर डालें तो यह स्थिति की पुनरावृत्ति ही है। लेकिन यदि बीते कुछ सालों में लापता होने वाले लोगों की संख्या पर नजर डालें तो कहा जाता है कि इस साल जनवरी में सामने आई लापता लोगों की संख्या ज्यादा नहीं है। इस बाबत दिल्ली पुलिस का कहना है कि जनवरी 26 में कुल 1,777 लोगों के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। प्रथम दृष्टया यह संख्या भले ही बढ़ी लगे, लेकिन जब पिछले दो सालों के आंकड़ों से इसकी तुलना की जाती है तो नई तस्वीर उभरती है। दरअसल, इन आंकड़ों की तह में जाएं तो दिल्ली का विशाल इलाका व सघन जनसंख्या घनत्व भी इसके मूल में है।

दरअसल, एक बड़ी आबादी रोजगार व अन्य कार्यों के लिए दिल्ली आती-जाती रहती है। दिल्ली पुलिस के आंकड़ों के अनुसार साल 2024 में करीब 24,893 लोग लापता हुए थे। यानी एक माह में औसतन 2,074 लोग। वहीं साल 2025 में ये संख्या 24,508 लोग लापता हुए। अर्थात? हर माह 2,042 लोग गुम हुए। इस दृष्टि से जनवरी, 26 का आंकड़ा इस संख्या से कम है। सवाल है कि 2026 के पहले माह के आंकड़ों को लेकर भय क्यों व्याप्त हुआ? दरअसल, पहले पंद्रह दिनों के आंकड़ों के हिसाब से दिल्ली में हर रोज 54 लोग लापता हो रहे थे। इन आंकड़ों के सामने आने के बाद लोगों ने इसके मूल में किसी संकट को देखा।

दिल्ली पुलिस के अनुसार ये आंकड़े स्थायी गुमशुदगी के नहीं होते।

कुछ लोग अल्पकाल के लिए कहीं चले जाते हैं और देर रात तक घर भी लौट आते हैं। पुलिस का यह भी कहना है कि राष्ट्रीय राजधानी में ऑनलाइन और ऐप आधारित सिस्टम के जरिये लोग जल्दबाजी में अपने परिजनों के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। मसलन यदि कोई बच्चा किसी कारणवश स्कूल से लौटने में देर कर दे, कोई व्यक्ति कुछ घंटों तक फोन संपर्क से कट जाए या कोई बुजुर्ग भटकने पर देर से घर पहुंचे तो लोग गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। ये कथित गुमशुदा लोग कुछ समय बाद घर तो लौट आते हैं, लेकिन लोग पुलिस डेटा को अपडेट नहीं करते। फलस्वरूप पुलिस आंकड़ों में उनकी गुमशुदगी बनी रहती है। पुलिस का दावा है कि लापता लोगों को खोजने की दर में लगातार सुधार हो रहा है। साल 2016 में जो 23,409 लोग लापता हुए थे, उनमें से करीब 85 फीसदी नौ साल के भीतर मिल गए। साल 2025 में दर्ज मामलों में 63 फीसदी लोगों को भी एक साल के भीतर तलाश लिया गया।इन आंकड़ों के सामने आने के बाद घर से निकलने के बाद सुरक्षा इंतजामों को लेकर तमाम तरह की सलाहें दी जाने लगीं। कुछ लोग देश के सिस्टम पर सवाल खड़े करने लगे। कुछ लोगों में भय से जुड़ी प्रतिक्रिया भी सामने आई।

लेकिन इस बाबत दिल्ली पुलिस द्वारा जारी आंकड़े भी अधिक चिंता बढ़ाने वाले नजर आए। प्रथम दृष्टया यह खबर परेशान करने वाली है, लेकिन पड़ताल में पाया गया कि यह स्थिति पिछले कुछ सालों के आंकड़ों के ही अनुरूप है।

बेरोजगारी भी बढ़ा सकता है खाद्य पदार्थों का आयात

पुष्परंजन शुक्ला

ऐसे समय में जब घरेलू खेती पहले से ही संत्रास में है, किसानों को मंडियों में घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी से 30 से 40 फीसदी कम दाम मिल रहे हैं, भारत के विशाल बाज़ार को सस्ते और बहुत...ऐसे समय में जब घरेलू खेती पहले से ही संत्रास में है, किसानों को मंडियों में घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी से 30 से 40 फीसदी कम दाम मिल रहे हैं, भारत के विशाल बाज़ार को सस्ते और बहुत ज़्यादा सब्सिडी वाले खेती उत्पादों के लिए और खोलने से खेती-बाड़ी पर बहुत बुरा असर पड़ेगा।शेक्सपियर के नाटकों में द्वंद्वात्मक कथानक की तरह, एक बड़ी दुविधा यह है कि किस पर विश्वास करें और किस पर नहीं। जहां एक ओर अमेरिकी कृषि मंत्री ब्रुक रोलिंस ने भारत के साथ एक बढ़िया व्यापार संधि -'अमेरिकी किसानों के लिए फायदेमंद है'- के लिए अपने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय वाणिज्य मिनिस्टर पीयूष गोयल ने भी अमेरिका के साथ 'ऐतिहासिक संधि' के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है और दोहराया है कि यह करते वक्त भारत के संवेदनशील कृषि एवं डेयरी क्षेत्र को सुरक्षित रखा गया है।

क्या यह दोनों लोकतंत्रों के लिए 'परस्पर जीत' वाली स्थिति है या यह जोर-जबरदस्ती और मनमानी का नतीजा है, इसकी पुष्टि तो विवरण से ही हो पाएगी। लेकिन जो बातें सार्वजनिक तौर पर चली हुई हैं, उन्होंने पहले ही देशभर की किसान यूनियनों की रीढ़ में सिहरन की लहर दौड़ा दी है। उनके पास ऐसी चिंता करने के लिए पर्याप्त कारण भी हैं।

ऐसे समय में जब घरेलू खेती पहले से ही संत्रास में है, किसानों को मंडियों में घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी से 30 से 40 फीसदी कम दाम मिल रहे हैं, भारत के विशाल बाज़ार को सस्ते और बहुत ज़्यादा सब्सिडी वाले खेती उत्पादों के लिए और खोलने से खेती-बाड़ी पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। अमेरिकी किसानों को पहले से ही हर साल भारी सब्सिडी मिलती है, जो कि तकरीबन 66,314 डॉलर प्रति किसान वार्षिक जितनी है (एग्रीकल्चरल रिसोर्स मैनेजमेंट सर्वे, 2020), यह उन्हें उतार-चढ़ावों से बचाती है। इसके अलावा, अमेरिकी प्रशासन वर्ष 2026 में फार्मर्स ब्रिज असिस्टेंस प्रोग्राम (एफबीए) के तहत किसानों को होने वाले प्रति एकड़ नुकसान की भरपाई हेतु 12 बिलियन डॉलर की मदद उत्पाद भुगतान मद के तहत देने की योजना बना रहा है। ट्रंप ने इसको 'वन बिग ब्यूटीफुल बिल' का नाम दिया है।ऐसे में जब अमेरिका भारत व्यापार संधि के विवरण का अभी इंतज़ार है, अमेरिका और भारत, दोनों पक्ष बड़े-बड़े दावे कर रहे हैं। ब्रुक रोलिंस ने तो सोशल मीडिया पर यह तक कह डाला है कि इस समझौते से 'भारत के विशाल बाज़ार को अमेरिकी कृषि उत्पादों का अधिक निर्यात हो पाएगा, जिससे कीमतें ऊपर उठेंगी और ग्रामीण अमेरिका में अधिक नकदी आएगी'। यह कथन मोटे तौर पर व्यापार समझौते की शर्तों के मुताबिक है, जिसका जिक्र ट्विटर पर अपनी पोस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति ने किया था कि अमेरिका में आयात होने वाले भारतीय उत्पादों पर टैरिफ 50 से घटाकर 18 परसेंट कर दी गई है और भारत में नॉन-टैरिफ बैरियर हटाने के अतिरिक्त अमेरिकी निर्यात पर आयात कर शून्य कर दिया गया जाएगा। इस बीच, भारत के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान किसानों को भरोसा दिला रहे हैं कि यह समझौता किसानों के हितों को 'सुरक्षित' रखने के बाद ही किया गया है।इन भरोसे के बावजूद, भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की खबर ने पहले ही किसान समुदाय को परेशान कर डाला है। भारत सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए, जो कोई अन्य जानकारी देने से बच रही है, कई किसान नेताओं ने शक जताया है कि क्या किसानों के हितों की रक्षा में वास्तव में हुई है। संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बयान में चेतावनी दी है कि आयात शुल्क शून्य होने से सस्ते आयातित उत्पादों की बाढ़ आ जाएगी, और इसलिए 12 फरवरी से नए विरोध प्रदर्शनों की धमकी दी है। किसान नेताओं का कहना है कि प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन 2020-21 के विरोध प्रदर्शनों की तर्ज पर होंगे।किसान समुदाय को इस बात का भी गुस्सा है कि बजट-2026 में कृषि आय को बढ़ाने के लिए ज़रूरी उपायों पर ज़्यादातर चुप्पी रही है, और पहले से ही संकट झेल रहे कृषि क्षेत्र की रक्षा के लिए लाल लकीर कहां खींची जाए, इस पर किसानों से कोई सलाह-मशविरा नहीं किया गया है। इसके अलावा, सबसे अमीर व्यापारिक समूह, ऑर्गेनाइज़ेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट (ओईसीडी) ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में अनुमान लगाया है कि भारतीय किसानों को 2000-01 और 2024-25 के बीच कुल मिलाकर 111 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है, लिहाजा किसानों के लिए एक और बड़ा झटका सहना मुश्किल होगा। हिमाचल प्रदेश में सेब बागवान संघ के अध्यक्ष हरीश चौहान ने चेतावनी दी है 'यह असहाय किसान समुदाय पर बड़े हथौड़े की मार जैसा होगा'।

स्वच्छ भारत मिशन को रफ़्तार देते इलेक्ट्रिक वाहन

कचरा संग्रहण

डा0 सुधीर कुमार

शहरों में कचरा ढुलाई में लगे डीजल-पेट्रोल व सीएनजी वाहनों की जगह विभिन्न चरणों में ई-वाहनों को लाना चाहिये। एक शोध के मुताबिक, इससे कचरा संग्रहण की घटती है। वहीं स्वच्छ भारत मिशन के प्रभाव और व्यापक हो सकते हैं। पीएम ई-ड्राइव जैसी योजनाएं इसमें मददगार होंगी।बीते कुछ वर्षों में स्वच्छ भारत मिशन से शहरी स्वच्छता में क्रांतिकारी बदलाव आया है। देश के लगभग सभी शहरों में घरों के दरवाजे से कचरे का संग्रहण (डोर-टू-डोर वेस्ट कलेक्शन) अब एक सामान्य और नियमित व्यवस्था बन चुकी है। दूसरी तरफ, 'फेम' और हालिया घोषित 'पीएम ई-ड्राइव' जैसी योजनाएं भारत के 'क्लीन मोबिलिटी' के लक्ष्य को आगे बढ़ा रही हैं। कचरा संग्रहण वाहनों के इलेक्ट्रिफिकेशन (पेट्रोल/डीजल/ सीएनजी वाहनों की जगह इ-वाहनों का उपयोग) से, ये दोनों प्रमुख राष्ट्रीय प्राथमिकताएं परस्पर जुड़ सकती हैं।

इससे कचरा संग्रहण वाहनों की परिचालन लागत घट सकती है व इन प्रदूषण-मुक्त वाहनों से स्वच्छ भारत मिशन के प्रभाव और व्यापक बनाये जा सकते हैं।भारतीय शहरों में सालाना करीब 1.4 से 1.6 लाख टन शहरी कचरा निकलता है। साल 2016 से 2024 के बीच, शहरी निकायों में कचरा संग्रहण में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है। राष्ट्रीय स्तर पर इसका दायरा 44 प्रतिशत वार्डों से बढ़कर अब 97 प्रतिशत वार्डों तक पहुंच गया है, जो लगभग पूर्ण-विस्तार के नजदीक है। इसी वजह से शहरी निकायों के वाहनों का बेड़ा देश में सबसे बड़े संगठित वाहन बेड़े में से एक बन गया है। हालांकि, देश में 70 प्रतिशत से अधिक कचरा 'जनगणना श्रेणी-1' के शहरों (1 लाख से अधिक आबादी) से निकलता है, जो सालाना 3-4 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है। काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वॉटर (सीईईडब्ल्यू) के हालिया शोध के अनुसार, बढ़ती जनसंख्या और कचरे की मात्रा में वृद्धि को देखते हुए इन शहरों को 2030 तक डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण के लिए 80,000 नए वाहन चाहिये।शहरी कचरा प्रबंधन के लिए आवंटित कुल बजट का करीब आधा हिस्सा

कचरा संग्रहण व ढुलाई पर खर्च होता है। इतने अधिक वित्तीय बोझ के अलावा डीजल या सीएनजी वाहनों से कचरा संग्रहण और ढुलाई का पर्यावरण पर असर पड़ता है। अमृतसर के उदाहरण के साथ सीईईडब्ल्यू का अध्ययन बताता है कि कचरा संग्रहण वाहनों का इलेक्ट्रिफिकेशन कितना लाभ दे सकता है।अभी अमृतसर में कचरा संग्रहण व ढुलाई में 200-220 चौपहिया डीजल वाहन इस्तेमाल होते हैं, जो रोजाना 400 टन से अधिक कचरे का प्रबंधन करते हैं। प्रतिदिन प्रति वाहन औसत उपयोग 15-20 किमी है। इस उपयोग स्तर पर इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन अपने पूरे जीवनकाल में मौजूदा वाहनों के मुकाबले 25-30 फीसदी किफायती साबित होंगे, जिससे नगर निगम का सालाना ईंधन खर्च 60-80 फीसदी कम होगा।भारतीय शहरों में आमतौर पर कचरा संग्रहण वाहन प्रतिदिन 15-55 किमी दूरी तय करते हैं, जिनमें तीन व चार पहिया वाहन शामिल हैं। प्रतिदिन प्रति वाहन 50-60 किमी अधिकतम उपयोग स्तर पर इ-तिपहिया वाहन सबसे किफायती विकल्प हैं, जबकि इलेक्ट्रिक चौपहिया वाहन डीजल व सीएनजी वाहनों के मुकाबले सस्ते पड़ते हैं। प्रत्येक इ-वाहन सालाना लगभग 83 किलोग्राम सूक्ष्म कणों (पीएम 2.5) और आधा टन नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन घटा सकता है।

कचरा संग्रहण वाहनों के इलेक्ट्रिफिकेशन का आधार काफी मजबूत है। चूंकि ये वाहन तय मार्गों पर चलते हैं और लौटकर डिपो में खड़े होते हैं, इसलिए इन्हें रात में चार्ज करना संभव है। इससे वाहनों की दूरी तय करने की चिंता खत्म होती है। कचरा संग्रहण के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल शुरू कर चुके हैं। इन सफलताओं को देश के सभी शहरों में लागू करने को एक सुनियोजित रोडमैप की जरूरत है।सबसे पहले, शहरी स्थानीय निकायों को पायलट प्रोजेक्ट्स के जरिए इ-वाहनों के प्रति भरोसे में लेना चाहिए। कचरा प्रबंधन में विशेष काम शामिल होते हैं, खास तौर पर गीले कचरे के प्रबंधन में। इसलिए, बढ़ावा देना चाहिए, दूसरे शहरों के अनुभवों से सीखने के साथ-साथ शहरस्तरीय कार्यशालाएं आयोजित हों। इससे अधिकारियों और वाहन संचालकों को जमीनी स्थितियों में इ-वाहनों की क्षमता, चार्जिंग जरूरतों और रखरखाव को समझने में मदद मिल सकती है।दूसरा, शहरों को कचरा संग्रहण वाहनों की जगह इलेक्ट्रिक वाहन लाने की चरणबद्ध योजनाएं बनानी चाहिए। शहरी निकाय अपने मौजूदा वाहनों की आयु, ईंधन के प्रकार और दैनिक उपयोग के आधार पर विवरण तैयार करें और पुराने वाहनों को हटाने के क्रम में इ-वाहन लाने का लक्ष्य तय करें। चरणबद्ध योजनाएं वाहन खरीद को राष्ट्रीय - राज्यों के इलेक्ट्रिक-मोबिलिटी लक्ष्यों के साथ तालमेल लाने में मदद करेंगी।तीसरा, नीतिगत प्रोत्साहनों का लक्ष्य बहुत सटीक होना चाहिए। राष्ट्रीय और राज्यस्तरीय ईवी नीतियां कचरा-संग्रहण वाहनों को विशेष सब्सिडी देकर शुरुआती लागत घटा सकती हैं।

शिवराजपुर में सिस्टम फेल: चालू बिजली के बीच हाई पावर ट्रांसफार्मर लूटा

कटर चला कर ट्रांसफार्मर गिराया, लाखों के उपकरण ले गए, इलाके में अंधेरा

स्वराज इंडिया ब्यूरो

शिवराजपुर/ बिल्हौर (कानपुर)। शिवराजपुर थाना क्षेत्र में कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल होती नजर आ रही है। शुक्रवार रात चालू बिजली आपूर्ति के दौरान दुबियाना गांव के पकरा पर लगे हाई पावर ट्रांसफार्मर को कटर से काटकर गिराया गया और लाखों रुपये के कॉपर पुर्जे व तेल चोरी कर लिया गया। यह वारदात सिर्फ चोरी नहीं, बल्कि सुरक्षा तंत्र और पुलिस गश्त की खुली नाकामी का प्रमाण है। रातभर चोर बेखौफ होकर वारदात करते रहे और सुबह किसानों ने जब ट्रांसफार्मर जमीन पर पड़ा देखा, तब जाकर घटना सामने आई। न बैरीकेडिंग बची, न निगरानी काम आई और न ही पुलिस की मौजूदगी दिखी।

जानकारी के मुताबिक पहले सुरक्षा घेरा तोड़ा गया, फिर तार काटकर ट्रांसफार्मर को पक्के चबूतरे से नीचे गिराया गया। इसके बाद कॉपर कॉइल और सैकड़ों लीटर तेल निकाल लिया गया। चोरी के चलते पूरे इलाके की बिजली सप्लाई ठप हो गई, ग्रामीण अंधेरे और आक्रोश में डूब गए। लगातार हो रही इन घटनाओं के बावजूद अब तक एक भी चोरी का खुलासा नहीं हो सका है। इससे अपराधियों के हौसले और बुलंद होते जा रहे हैं।

पुरानी फाइलें धूल खा रहीं, चोर दे रहे खुली चुनौती

ऊधौ नेवादा गांव में ग्राम प्रधान के घर के बाहर से चोरी हुई दो बाइकों का मामला भी अब तक अधर में लटका है। पुरानी फाइलें ठंडे बस्ते में हैं और चोर नई वारदात कर पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। शिवराजपुर पुलिस की कार्यशैली पर अब गंभीर सवाल उठने लगे हैं। पुलिस का कहना है कि जांच जारी है, लेकिन सवाल यही है–जब सिस्टम ही फेल है, तो भरोसा किस पर?

यह भी जान लीजिए

- **6 जनवरी:** लालपुर गांव में ट्रांसफार्मर चोरी
- **29 जनवरी:** नसीरपुर गांव में दो ट्रांसफार्मर खाली
- **5 फरवरी:** नसिरापुर में ट्यूबवेल ट्रांसफार्मर निशाना
- अब दुबियाना गांव में हाई पावर ट्रांसफार्मर लूट

झूला किराये के विवाद में जायरीनों पर हमला, दो गंभीर घायल

स्वराज इंडिया ब्यूरो

बिल्हौर (कानपुर)। मकनपुर दरगाह पर जियारत के बाद बच्चों को झूला झुलाने गए जायरीनों पर झूला ठेकेदार और उसके साथियों ने हमला कर दिया। झूला किराये को लेकर हुए विवाद में लाठी-डंडों से की गई मारपीट में दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर चार नामजद समेत कुल 14 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

मकनपुर निवासी रिजनावल करीम के अनुसार, उसका बेटा फैजान अहमद दरगाह पर जियारत के बाद बच्चों को झूला झुलाने गया था। इसी दौरान झूले के किराये को लेकर ठेकेदार से कहासुनी हो गई। आरोप है कि झूला ठेकेदार भूरा ने अपने साथियों संतराम, अमन, समीर और करीब दस अज्ञात लोगों के साथ मिलकर फैजान पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया।

शोर सुनकर फैजान का छोटा भाई जमन

➪ 4 नामजद, 10 अज्ञात पर केस दर्ज, पुलिस कर रही आरोपियों की तलाश

अहमद बीच-बचाव के लिए पहुंचा तो हमलावरों ने उसे भी बेरहमी से पीट दिया और मरणासन्न हालत में छोड़ दिया। वारदात के बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। इस संबंध में इंस्पेक्टर अरौल जनार्दन यादव ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर नामजद और अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस टीमें गठित की गई हैं और जल्द गिरफ्तारी की जाएगी।

बीएसपी प्रभारी बनने पर विनय गौतम ने दरगाह पर टेका माथा

2027 में बीएसपी सरकार बनने की मांगी दुआ

स्वराज इंडिया ब्यूरो

बिल्हौर (कानपुर)। बहुजन समाज पार्टी ने सक्रिय नेता एवं अधिवक्ता विनय कुमार गौतम पर भरोसा जताते हुए उन्हें बिल्हौर विधानसभा का प्रभारी नियुक्त किया है। प्रभारी बनाए जाने के बाद विनय कुमार गौतम ने बिल्हौर बार एसोसिएशन के पूर्व महामंत्री महेंद्र सिंह कुशवाहा एवं समर्थकों के साथ मकनपुर स्थित जिंदा शाह मदार की दरगाह पर माथा टेककर आशीर्वाद लिया।

दरगाह पर सज्जादानशीं शोएब गाजी ने परंपरा के अनुसार पगड़ी बांधकर उन्हें सम्मानित किया। इसके बाद विनय गौतम ने मकनपुर में बीएसपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति और रूपरेखा तैयार की। बैठक में कहा कि बहुजन समाज पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी और 2027 में बीएसपी की सत्ता में वापसी तय है।

उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और जनता के मुद्दों को प्राथमिकता से उठाने का आह्वान किया। इस मौके पर वरिष्ठ बसपा नेता विनोद राय, रजनीश, नजीबुल बाकी, रमेश पाल, प्रेम चंद्र बौद्ध, अमित कमल समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।

सरकार बनी तो एक्सप्रेस-वे का कट खुलवाएंगे

मकनपुर से होकर गुजरने वाले आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर अब तक कोई कट नहीं दिया गया है, जबकि जिंदा शाह मदार की दरगाह पर साल में दो उर्स और एक सरकारी मेला लगता है। ऐसे में उर्स और मेलों के दौरान जायरीनों को आने-जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बीएसपी प्रभारी विनय गौतम ने दरगाह से जुड़े लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा कि बीएसपी की सरकार बनने पर मकनपुर अंडरपास पर हाईवे का उतार दिलवाया जाएगा, ताकि जनता और जायरीनों को सुविधा मिल सके।

फिल्म 'घूसखोर पंडत' के विरोध में सनातन मठ मंदिर रक्षा समिति

ज्ञापन देकर मुकदमा दर्ज करने की मांग

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर।आगामी फिल्म और वेब सामग्री 'घूसखोर पंडत' के शीर्षक तथा उसके प्रचार को लेकर सनातन मठ मंदिर रक्षा समिति, उत्तर प्रदेश ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। समिति के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने थाना किदवई नगर पहुंचकर थानाध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा और फिल्म से जुड़े निर्माता, निर्देशक तथा अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किए जाने की मांग की।समिति द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र में कहा गया कि फिल्म का शीर्षक समाज में सम्मानित और पूजनीय माने जाने वाले सांस्कृतिक संबोधन 'पंडित' को नकारात्मक, आपराधिक और भ्रष्ट छवि के रूप में प्रस्तुत करता है। इससे न केवल ब्राह्मण समाज, बल्कि सनातन धर्म से जुड़े करोड़ों श्रद्धालुओं की धार्मिक और सामाजिक भावनाएं आहत हुई हैं। समिति ने इसे जातिसूचक शब्द के माध्यम से पूरे समाज को बदनाम करने का प्रयास बताया, जिससे सामाजिक सौहार्द और शांति भंग होने की आशंका उत्पन्न हो गई है।सनातन मठ मंदिर रक्षा समिति के अध्यक्ष अजय कुमार द्विवेदी के निर्देश पर उपाध्यक्ष सुधीर द्विवेदी के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि फिल्म निर्माता संघ द्वारा संबंधित फिल्म और वेब सामग्री के निर्माताओं को नोटिस जारी किया जा चुका है। नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि फिल्म के शीर्षक के उपयोग के लिए निर्धारित नियमों के अंतर्गत आवश्यक अनुमति प्राप्त नहीं की गई, जो नियमों का सीधा उल्लंघन है।इस संबंध में समिति के उपाध्यक्ष सुधीर द्विवेदी ने कहा कि 'घूसखोर पंडित' कोई सामान्य शीर्षक नहीं है, बल्कि यह सनातन धर्म और ब्राह्मण समाज की छवि को धूमिल करने का प्रयास है। 'पंडित' जैसे पूजनीय शब्द को अपराध और भ्रष्टाचार से जोड़ना अत्यंत आपत्तिजनक है और यह सामाजिक वैमनस्य फैलाने की मंशा को दर्शाता है। जब फिल्म निर्माता संघ स्वयं नियमों के उल्लंघन की पुष्टि कर चुका है, तो यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं, बल्कि कानून को चुनौती देने का मामला बन जाता है।उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जानबूझकर भड़काऊ शीर्षक के माध्यम से समाज को विभाजित करने का प्रयास किया जा रहा है। यदि समय रहते सख्त कार्रवाई नहीं की गई, तो इसके गंभीर सामाजिक परिणाम सामने आ सकते हैं। समिति धर्म, संस्कृति और सामाजिक गरिमा की रक्षा के लिए कानूनी संघर्ष पूरी दृढ़ता से जारी रखेगी।ज्ञापन में यह भी कहा गया कि बिना अनुमति और आपत्तिजनक शीर्षक के साथ सामाजिक माध्यमों तथा अन्य डिजिटल मंचों पर किया जा रहा प्रचार कानपुर नगर सहित अन्य क्षेत्रों में जातिगत तनाव उत्पन्न कर सकता है, जो कानून-व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती है।इस मौके पर समिति के महामंत्री प्रेम कुमार दीक्षित, रविशंकर तिवारी, अक्षय नारायण तिवारी, मनीष त्रिपाठी, आकाश तिवारी, उत्कर्ष बाजपेई, जितेंद्र अवस्थी सहित अनेक सामाजिक कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। सभी ने एक स्वर में समाज को विभाजित करने वाले ऐसे कंटेंट की कड़ी निंदा करते हुए दोषियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की।

अभिव्यक्ति की आज़ादी और सामाजिक सम्मान

फ़िल्मों और डिजिटल कंटेंट के माध्यम से 'पंडित/ब्राह्मण' शब्द को लगातार अपमान और नकारात्मकता के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया जाना गंभीर चिंता का विषय है। यह प्रवृत्ति अब रचनात्मक अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि समाज को बाँटने वाली एक सोची-समझी वैचारिक और राजनीतिक रणनीति का रूप ले चुकी है। अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर किसी एक समाज को बार-बार निशाना बनाना न तो संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप है और न ही सामाजिक सौहार्द के हित में। केंद्र सरकार और सेंसर बोर्ड को ऐसी जातिसूचक एवं विद्वेष फैलाने वाली फिल्मों पर तत्काल संज्ञान लेकर सख़्त कार्रवाई करनी चाहिए। कला का उद्देश्य जोड़ना है, तोड़ना नहीं। सम्मान से कोई समझौता नहीं होगा। **प्रवीण कुमार शुक्ल**

अराजकता का अड्डा बना नगर निगम बजरिया कब्रिस्तान !

बजरिया के अंतर्गत आने वाले कब्रिस्तान में बन रही झोपडियां

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर ।नगर निगम जोन-4 अंतर्गत आने वाला बजरिया कब्रिस्तान इस समय अराजकता का अडडा बन गया है। इसके अंदर कई झोपडिया बनाकर लोग रहे हैं, इसमें संदिग्ध गतिविधियों का अंजाम दिया जा रहा है। इसमें अनजान लोगों का आवागमन भी होता है।

नगर निगम कब्रिस्तान से करीब 3 साल पहले मेयर प्रमिला पांडेय ने पूरी अवैध बस्ती हटाई थी, इसके बाद अनदेखी के चलते फिर से लोग कब्जा कर रहे हैं। वहीं, बीते माह बिना किसी जरूरत के ठेकेदार के द्वारा वहां पर निर्माण कार्य शुरू किया गया। बताया गया कि मिटटी में आने वाले लोगों के बैठने के लिए स्थान बनाया जा रहा है जबकि स्थानीय लोगों ने बताया कि वहां पर इसकी कोई आवश्यकता प्रतीत भी नहीं होती है, जब कि गेट और कई जगह बाउंड्री ध्वस्त है। उसपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पार्षद गोविंद शुक्ला ने बताया कि बिना बताए ठेकेदार मनमाने ढंग से निर्माण कर रहे हैं, इसका निरीक्षण करके उच्चाधिकारियों को अवगत कराया जाएगा। वहीं, मुख्य अभियंता जैदी ने बताया कि निर्माण कार्य की जानकारी करके कार्रवाई की जाएगी।

तीन दिन से तेंदुए की मौजूदगी, शाम होते ही घरों में सिमट रहे ग्रामीण

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। ब्लॉक राजपुर की बीहड़ पट्टी के पिचौरा, बिजहरा और बेहमई गांवों के जंगलों में पिछले तीन दिनों से तेंदुआ देखे जाने की खबर से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। तेंदुए की मौजूदगी के चलते गांवों में डर इस कदर फैल गया है कि शाम ढलते ही लोग घरों में दुबकने को मजबूर हो रहे हैं, जबकि खेतों और जंगल की ओर अकेले जाने से लोग कतरा रहे हैं। ग्रामीणों द्वारा सूचना दिए जाने पर वन विभाग की टीम ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन अब तक तेंदुए का कोई स्पष्ट सुराग नहीं मिल सका है।

बीहड़ पट्टी के जंगलों में तेंदुआ दिखने से दहशत, वन विभाग की टीम का सर्च ऑपरेशन जारी

- राजपुर ब्लॉक की बीहड़ पट्टी में तेंदुए की दहशत
- पिचौरा, बिजहरा और बेहमई गांव सबसे ज्यादा प्रभावित
- सड़क पर तेंदुआ दिखने से राहगीरों में अफरा-तफरी
- जंगल में बकरियां चराने गए ग्रामीण ने भी देखा तेंदुआ
- तेंदुए की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल

कस्बा राजपुर निवासी ध्रुव सिंह ने बताया कि बीते गुरुवार रात करीब 9 बजे वह जैनपुर मंदिर के महंत शिवपाल दास महाराज के साथ चार पहिया वाहन से बेहमई से राजपुर लौट रहे थे। बिजहरा गांव के सामने जैसे ही उन्होंने आगे चल रहे बाइक सवार दंपति को ओवरटेक किया, सड़क के बीच बैठे तेंदुए को देखकर सभी के होश उड़ गए। वाहन की लाइट पड़ते ही तेंदुआ जंगल की ओर भाग निकला।वहीं, गुवार गांव निवासी रामवली पाल ने बताया कि दो दिन पूर्व वह बकरियों को चराने जंगल गए थे, तभी झाड़ियों के बीच से अचानक तेंदुआ निकलता दिखाई दिया। शोर मचाने पर तेंदुआ वापस जंगल में चला गया। लगातार तेंदुआ दिखने की घटनाओं के बाद ग्रामीणों में भय व्याप्त है। शाम होते ही गांवों में सन्नाटा पसर जाता है। इसी बीच किसी ग्रामीण द्वारा चार पहिया वाहन से झाड़ियों में बैठे तेंदुए की तस्वीर भी ली गई, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। ग्रामीणों ने वन विभाग से तेंदुए को जल्द से जल्द पकड़वाने और क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की मांग की है।इस संबंध में वन विभाग के रेंजर स्वामीदीन ने बताया कि तेंदुआ देखे जाने की सूचना मिली है। जंगलों में टीम भेजकर लगातार निगरानी की जा रही है। ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। उन्होंने अपील की कि लोग अकेले जंगल न जाएं, जरूरत पड़ने पर समूह में जाएं और हाथों में लाठी-डंडे रखें, ताकि किसी भी संभावित खतरे से बचा जा सके।

इन्हीं जंगलों के बीच छिपा बताया जा रहा तेंदुआ

स्कूल गेट पर ताला अभिभावकों का फूटा गुस्सा

» प्रधानाध्यापक की मनमानी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। राजपुर ब्लॉक क्षेत्र के दमनपुर स्थित सिविलियन विद्यालय में शिक्षा व्यवस्था की गंभीर अनदेखी का मामला सामने आया है। समय पर विद्यालय न खुलने के कारण रोजाना नौनिहाल बच्चों को स्कूल के गेट पर खड़े होकर शिक्षकों का इंतजार करना पड़ रहा है। शुक्रवार को इसी लापरवाही का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। वायरल वीडियो की स्वराज इंडिया पुष्टि नहीं करता है।

जानकारी के अनुसार बच्चे तय समय पर विद्यालय पहुंच जाते हैं, लेकिन प्रधानाध्यापक राज नारायण की मनमानी के चलते स्कूल का गेट काफी देर तक बंद रहता है। गेट तभी खोला जाता है जब प्रधानाध्यापक विद्यालय पहुंचते हैं, तब जाकर पढ़ाई शुरू होती है। दमनपुर गांव के चंद्र प्रताप सिंह, राम सिंह, जगदीश सिंह, आराम सिंह और कैलाश सिंह सहित दर्जनों अभिभावकों ने आरोप लगाया

कि जब उन्होंने प्रधानाध्यापक से देरी से आने का कारण पूछा तो उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया और अभिभावकों को विद्यालय से बाहर निकाल दिया।

अभिभावकों का कहना है कि फरवरी माह शुरू हो चुका है, लेकिन बच्चों का पाठ्यक्रम अभी तक अधूरा है। घर पर पढ़ाई की जांच करने पर बच्चे सामान्य प्रश्नों के उत्तर भी नहीं दे पा रहे हैं। इससे बच्चों के भविष्य को लेकर अभिभावकों में गहरी चिंता है। विद्यालय में करीब 118 बच्चे पंजीकृत बताए जा रहे हैं। घटना से आक्रोशित अभिभावकों ने नोकझोंक का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया और शिक्षा विभाग से कठोर कार्रवाई की मांग की है। वीडियो वायरल होने के बाद विभागीय अधिकारियों की भी किरकिरी हो रही है। इस संबंध में राजपुर ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि वायरल वीडियो की जानकारी मिली है। पूरे प्रकरण की जांच कर दोषी पाए जाने वाले शिक्षकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

भोगनीपुर पुलिस-एसओजी ने 10 हजार के इनामिया को किया गिरफ्तार

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। महिला से जुड़े अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत भोगनीपुर पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता मिली है।पुलिस ने महिला को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में वांछित 10 हजार रुपये के इनामिया अभियुक्त राहुल यादव उर्फ अंकित को गिरफ्तार कर लिया है।पुलिस के अनुसार अभियुक्त राहुल यादव उर्फ अंकित निवासी ग्राम उलरापुर, थाना रूरा, जनपद कानपुर देहात थाना भोगनीपुर में दर्ज मुकदमा संख्या 47/2025 धारा 137(2), 87, 61(2) बीएनएस में वांछित था। उसकी गिरफ्तारी शनिवार सुबह 08:35 बजे बड़ौली मोड़ से करीब 200 कदम पहले की गई। बताया गया कि अभियुक्त पर महिला को फुसलाकर ले जाने का आरोप है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास भी रहा है। उसके खिलाफ मध्यप्रदेश के भिंड जिले समेत कानपुर देहात के विभिन्न थानों में कई मुकदमे दर्ज हैं।गिरफ्तारी के दौरान अभियुक्त के पास से कोई आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई है।

औचक निरीक्षण: गौवंश आश्रय स्थल में लापरवाही पर सख्त हुए सीडीओ

खामियां मिलने पर व्यवस्थाएं तत्काल दुरुस्त करने के निर्देश

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। विकास खंड अकबरपुर में संचालित अस्थायी गौवंश आश्रय स्थल नरिहा का मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) विधान जायसवाल ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान गौवंशों के रख-रखाव, भोजन, पेयजल, साफ-सफाई और स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाओं में पाई गई खामियों पर उन्होंने नाराजगी जताई और जिम्मेदार अधिकारियों को त्वरित सुधार के सख्त निर्देश दिए।

सीडीओ ने बताया कि आश्रय स्थल में कुल 57 गौवंश संरक्षित हैं, जिनमें 2 नर और 55 मादा हैं। सभी गौवंशों

की ईयर टैगिंग शत-प्रतिशत पाई गई। उन्होंने चारा, भूसा, हरा चारा और पेयजल की उपलब्धता का जायजा लेते हुए निर्देशित किया कि गौवंशों को समय से और पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया जाए।

- औचक निरीक्षण में व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा
- 57 गौवंश संरक्षित, ईयर टैगिंग 100प्रतिशत
- समय से पौष्टिक आहार और स्वच्छ पेयजल के निर्देश
- स्वास्थ्य निगरानी, उपचार और साफ-सफाई पर सख्ती
- लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी

निरीक्षण के दौरान सीडीओ ने गौवंशों के स्वास्थ्य की नियमित निगरानी, बीमार पशुओं का तत्काल उपचार, टीकाकरण और दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया। साथ ही गौशाला परिसर की साफ-सफाई, शेड की स्थिति, नांद, जल व्यवस्था, जल निकासी और गोबर निस्तारण को व्यवस्थित रखने के निर्देश दिए, ताकि पशुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो।उन्होंने स्पष्ट किया कि गौसंरक्षण और पशु कल्याण से जुड़ी शासन की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन प्राथमिकता है और इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिम्मेदार अधिकारियों को नियमित निरीक्षण और मॉनिटरिंग के निर्देश भी दिए गए। निरीक्षण के समय जिला विकास अधिकारी, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी और गौशाला कर्मचारी मौजूद रहे।

रसूलाबाद में सपा प्रदेश अध्यक्ष का जोरदार स्वागत

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। उत्तर प्रदेश में एसआईआर के नाम पर पीडीए समाज के वोट काटने की साजिश की जा रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी का एक-एक कार्यकर्ता अब चौकन्ना है। अपने एक भी वोट को कटने नहीं दिया जाएगा। यह बाते समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने रसूलाबाद में कहीं।

प्रदेश अध्यक्ष का काफिला जैसे ही रसूलाबाद विधानसभा क्षेत्र से गुजरा, कस्बे में सपा के वरिष्ठ नेता हाजी फैजान खान की अगुवाई में सैकड़ों सपाइयों ने उनका भव्य स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अब भाजपा यह समझ चुकी है कि 2027 में उसकी दाल गलने वाली नहीं है, इसलिए वह तरह-तरह के फरेब कर रही है। ट्यूनी मिस्त्री, कलीम कुरैशी, रीटू यादव, अजयपाल यादव, रहीस निजामी सहित बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे।

ई-रिक्शा की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत

» हादसे में एक अन्य युवक गंभीर घायल, सीएचसी रसूलाबाद में भर्ती

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। जनपद में सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला बिल्हौर थाना क्षेत्र का है, जहां तेज रफ्तार और लापरवाही से आ रहे एक ई-रिक्शा ने बाइक को सीधी टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई और परिजनों में कोहराम मच उठा।

प्राप्त जानकारी के अनुसार दलेरपुर गांव निवासी जयकेश गांव के ही साथी अमित के साथ बाइक से शहबाजपुर की ओर जा रहा था। जैसे ही उनकी बाइक बर्रा-ठर्रा गांव के सामने रामनगर मार्ग पर पहुंची, तभी सामने से आ रहे ई-रिक्शा ने तेज गति और

लापरवाही से बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर के बाद जयकेश सड़क पर गिर पड़ा और गंभीर चोटों के चलते उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि अमित दूर जा गिरा और बुरी तरह घायल हो गया। आसपास मौजूद ग्रामीण तत्काल मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। दोनों को आनन-फानन में सीएचसी रसूलाबाद ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने जयकेश को मृत घोषित कर दिया। घायल अमित का उपचार चल रहा है।

इस संबंध में कोतवाल सतीश कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर मिलने पर ई-रिक्शा चालक के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि इस मार्ग पर ई-रिक्शा और अन्य वाहनों की तेज रफ्तार आवाजाही आम बात हो गई है। यातायात नियंत्रण के अभाव में आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। लोगों ने प्रशासन से इस मार्ग पर सख्त ट्रैफिक व्यवस्था और निगरानी की मांग की है।

दुष्कर्म के आरोपी को घर से दबोचा

कानपुर देहात। भोगनीपुर पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में वांछित चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी लंबे समय से फरार था।पुलिस के मुताबिक थाना भोगनीपुर में दर्ज दुष्कर्म के केस के तहत आरोपी राजा संखवार (22) निवासी ग्राम हलधरपुर की तलाश की जा रही थी। पीड़िता की ओर से माननीय न्यायालय में दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप है कि आरोपी ने महिला के साथ जबरन दुष्कर्म किया और विरोध करने पर मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। घटना के बाद से आरोपी फरार चल रहा था। शुक्रवार को भोगनीपुर

पुलिस टीम ने छापा मार कर आरोपी को उसके घर के बाहर से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक अमेन्द्र बहादुर सिंह और हेड कांस्टेबल वीरेंद्र कुमार शामिल रहे।

2027 की बिसात बिछाने में जुटी बसपा

मायावती का 'कमबैक प्लान' कितना असरदार?

बसपा अब रक्षात्मक नहीं, बल्कि आक्रामक राजनीतिक लाइन लेने की तैयारी में

» मुख्य संवाददाता, स्वराज इंडिया

लखनऊ। लखनऊ में हुई बहुजन समाज पार्टी की हालिया बैठक महज़ एक संगठनात्मक औपचारिकता नहीं, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बसपा के राजनीतिक पुनरुत्थान की स्पष्ट कोशिश के तौर पर देखी जा रही है। लंबे समय से हाशिये पर जा चुकी पार्टी अब एक बार फिर सियासी मैदान में खुद को प्रासंगिक साबित करने की रणनीति पर काम कर रही है।बैठक से पहले प्रेस वार्ता में मायावती के बयान इस ओर इशारा करते हैं कि बसपा अब रक्षात्मक नहीं, बल्कि आक्रामक राजनीतिक लाइन लेने की तैयारी में है। धर्म और जाति की राजनीति पर हमला कर उन्होंने सीधे तौर पर सत्ताधारी दल को घेरने की कोशिश की, साथ ही खुद को ‘विकल्प की राजनीति’ के रूप में पेश किया। यह रणनीति उस तबके को साधने की है जो मौजूदा राजनीति से असहज है, लेकिन अभी तक किसी मजबूत विकल्प की तलाश में रहा है।

संगठन पर फोकस- मजबूरी या रणनीति?

बसपा की सबसे बड़ी कमजोरी बीते चुनावों में संगठनात्मक शिथिलता रही है। लखनऊ बैठक में जोनल से लेकर विधानसभा प्रभारियों तक की मौजूदगी यह बताने की कोशिश है कि पार्टी जमीनी ढांचे को फिर से खड़ा करना चाहती है। बूथ स्तर की बात करना इस बात का संकेत है कि बसपा अब मान रही है कि केवल सोशल इंजीनियरिंग नहीं, बल्कि सक्रिय कैडर ही चुनावी सफलता की कुंजी है।

सोशल इंजीनियरिंग 2.0 की तैयारी

सूत्रों के मुताबिक ब्राह्मण और मुस्लिम मतदाताओं पर विशेष फोकस की चर्चा यह बताती है कि बसपा अपने पुराने 'दलित-ब्राह्मण' फॉर्मूले को नए संदर्भ में फिर से आजमाने की सोच में है। साथ ही सपा के कोर वोटर माने जाने वाले मुस्लिम और यादव समाज के असंतुष्ट वर्ग पर नजर रखना, विपक्षी वोट बैंक में सेंध लगाने की रणनीति मानी जा सकती है। हालांकि सवाल यह है कि क्या यह वर्ग बसपा को विश्वसनीय विकल्प मानेगा?

आकाश आनंद और अगली पीढ़ी का संकेत

बैठक में आकाश आनंद की मौजूदगी को केवल औपचारिक नहीं माना जा रहा। यह संदेश भी है कि बसपा नेतृत्व भविष्य की पीढ़ी को धीरे-धीरे आगे लाने की तैयारी में है। 2027 के बाद की राजनीति को देखते हुए यह कदम पार्टी की दीर्घकालिक योजना का हिस्सा हो सकता है।

चुनौती बड़ी, राह मुश्किल

हालांकि बसपा के सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं। लगातार चुनावी पराजयों से कार्यकर्ताओं का मनोबल, सीमित मीडिया स्पेस और संसाधनों की कमी पार्टी के लिए बड़ी बाधा हैं। इसके अलावा भाजपा बनाम सपा की सीधी लड़ाई के बीच बसपा को अपनी अलग और प्रभावी पहचान बनानी होगी।

आखिरी मौके की तरह...

लखनऊ की बैठक और मायावती के बयान साफ संकेत देते हैं कि बसपा 2027 को आखिरी मौके की तरह देख रही है। संगठन को सक्रिय करना, पुराने सामाजिक समीकरणों को नए सिरे से गढ़ना और खुद को तीसरे विकल्प के रूप में स्थापित करना—यही बसपा की मुख्य रणनीति है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या यह रणनीति ज़मीनी हकीकत में वोट में तब्दील हो पाएगी, या फिर यह कोशिश भी सिर्फ बैठक और बयानों तक सिमट कर रह जाएगी? यही 2027 की राजनीति का सबसे बड़ा सस्पेंस है।

बोर्ड परीक्षा: डबल लॉक व्यवस्था बदली, कई प्रधानाचार्यों ने छोड़ा केंद्र व्यवस्थापक पद

नए नियमों से केंद्र व्यवस्थापकों की मनमानी खत्म, प्रश्नपत्रों की सुरक्षा में स्टेटिक मजिस्ट्रेट और पुलिस की अहम भूमिका

» मुख्य संवाददाता, स्वराज इंडिया

फर्रुखाबाद। माध्यमिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज द्वारा बोर्ड परीक्षाओं को नकलविहीन और पारदर्शी बनाने के लिए लागू किए गए नए नियमों के चलते जनपद में परीक्षा केंद्रों पर सख्ती बढ़ा दी गई है। अब केंद्र व्यवस्थापक अपनी मर्जी से प्रश्नपत्रों के डबल लॉक को न तो खोल सकेंगे और न ही बंद कर सकेंगे। बदली हुई व्यवस्था से कुछ कॉलेजों के प्रधानाचार्य असहज दिखे और उन्होंने केंद्र व्यवस्थापक पद से किनारा कर लिया। उनके स्थान पर अन्य कॉलेजों के प्रधानाचार्यों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। परिषद और शासन की मंशा स्पष्ट है कि वर्ष 2026 की हाईस्कूल व इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाएं पूरी तरह शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और नकलविहीन ढंग से संपन्न कराई जाएं।

- केंद्र व्यवस्थापक अब प्रश्नपत्रों के डबल लॉक स्वयं नहीं खोल सकेंगे
- कई प्रधानाचार्यों ने जिम्मेदारी छोड़ी, नए केंद्र व्यवस्थापक नियुक्त
- स्ट्रांग रूम में चार डबल लॉक युक्त अलमारियां अनिवार्य
- चाबी व्यवस्था में स्टेटिक मजिस्ट्रेट और पुलिस की निर्णायक भूमिका
- स्ट्रांग रूम खोलने-बंद करने का समय लॉग बुक में दर्ज होगा
- लॉग बुक पुलिस अभिरक्षा में रहेगी
- 18 फरवरी से शुरू होंगी हाईस्कूल-इंटरमीडिएट परीक्षाएं
- यूपी सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 के तहत सख्त कार्रवाई की चेतावनी

18 फरवरी से शुरू होने वाली बोर्ड परीक्षा के आयोजन को लेकर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में अपर जिलाधिकारी (वि./रा.), अपर पुलिस अधीक्षक, जिला विद्यालय निरीक्षक, जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेट तथा जनपद के 78 परीक्षा केंद्रों पर तैनात स्टेटिक मजिस्ट्रेट मौजूद रहे। बैठक में जिला विद्यालय निरीक्षक ने स्टेटिक मजिस्ट्रेट को निर्देश दिए कि परीक्षा तिथि से पूर्व सभी केंद्रों पर आधारभूत सुविधाएं फर्नीचर, वॉयस रिकॉर्डर युक्त सीसीटीवी कैमरे, हाईस्पीड इंटरनेट, पेयजल, शौचालय, विद्युत की स्थायी व वैकल्पिक व्यवस्थासुनिश्चित कर ली जाए।

डबल लॉक और स्ट्रांग रूम की नई व्यवस्था

प्रश्नपत्रों के लिए स्ट्रांग रूम में चार डबल लॉक युक्त अलमारियां अनिवार्य की गई हैं। इनमें से रिजर्व प्रश्नपत्रों वाली चौथी अलमारी के प्रथम लॉक की एक चाबी स्टेटिक मजिस्ट्रेट और दूसरी चाबी केंद्र व्यवस्थापक के पास रहेगी, जबकि दूसरे लॉक की चाबी संबंधित थानाध्यक्ष या उनके द्वारा नामित इंस्पेक्टर की अभिरक्षा में रहेगी। स्ट्रांग रूम के लिए अलग से लॉग बुक तैयार की जाएगी, जिसमें खोलने और बंद करने का समय, संबंधित अधिकारी/कर्मचारी का नाम व विवरण दर्ज किया जाएगा। यह लॉग बुक केंद्र पर तैनात पुलिस बल की अभिरक्षा में रखी जाएगी।जिलाधिकारी ने सभी मजिस्ट्रेटों को शासनादेशों और उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 के प्रावधानों का गंभीरता से पालन करने के निर्देश दिए। किसी भी आपात स्थिति में तत्काल संबंधित जोनल/सेक्टर मजिस्ट्रेट, जिला विद्यालय निरीक्षक या जनपदीय कंट्रोल रूम (05692-234153) तथा कंट्रोल रूम प्रभारी (9450109285) को सूचना देने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सोशल मीडिया या सार्वजनिक रूप से किसी भी प्रकार की ब्रीफिंग, फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी पर सख्त रोक रहेगी। अपर पुलिस अधीक्षक ने परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त सशस्त्र पुलिस बल की तैनाती और सभी अधिकारियों से निर्देशों का अध्ययन कर परीक्षा को नकलविहीन कराने का आह्वान किया।

भाजपा जिला व महानगर अध्यक्ष की घोषणा जल्द

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

अयोध्या। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक 98 जिलों में से 84 जिलों के अध्यक्षों की घोषणा हो चुकी है। अब केवल 14 जिलों में जिला अध्यक्षों की घोषणा शेष है, जिनमें अवध क्षेत्र के अयोध्या जिला व महानगर, अंबेडकरनगर, गोंडा और लखीमपुर शामिल हैं।

पार्टी के संगठनात्मक सूत्रों के अनुसार, शेष जिलों के अध्यक्षों की घोषणा 7 से 10 फरवरी के बीच किसी भी समय की जा सकती है। इसके बाद 17 फरवरी तक क्षेत्रीय अध्यक्षों का चयन और मनोनयन किया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि इसके बाद 25 फरवरी तक प्रदेश संगठन की नई टीम भी घोषित कर दी जाएगी। संगठन में इस बार बड़े स्तर पर बदलाव के संकेत हैं। अयोध्या में जिला और महानगर अध्यक्ष पद को लेकर कार्यकर्ताओं और नेताओं में उत्सुकता बनी हुई है। सभी की निगाहें अब पार्टी नेतृत्व के अंतिम फैसले पर टिकी हैं।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर और हापुड़ एसएसपी को किया तलब

कोर्ट ने हत्या के मामले में पुलिस पर उठाए गंभीर सवाल

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हत्या के एक गंभीर मामले में पुलिस की भूमिका पर कड़ी नाराज़गी जताते हुए गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर और हापुड़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। कोर्ट ने गैर-जमानती वारंट की तामील में घोर लापरवाही पाए जाने पर इसे न्यायिक प्रक्रिया में बाधा और पुलिसकर्मी-अपराधी की संभावित सांठगांठ का मामला बताया है।

यह आदेश जस्टिस सलिल कुमार राय और जस्टिस सत्यवीर सिंह की खंडपीठ ने हत्या के मामले में दोषसिद्ध कौशल किशोर उर्फ बाबा की अपील की सुनवाई के दौरान पारित किया। कोर्ट ने दोनों वरिष्ठ अधिकारियों को 12 फरवरी, 2026 को दोपहर 2 बजे अनिवार्य रूप से उपस्थित होने को कहा है।कोर्ट के समक्ष सूरजपुर थाना प्रभारी ने रिपोर्ट दाखिल कर कहा कि आरोपी का पता सत्यापित नहीं हो सका, इसलिए गैर-जमानती वारंट वापस किया जा रहा है। हालांकि, इसी मामले में आरोपी कौशल किशोर ने 10 जनवरी को स्वयं हलफनामा दाखिल कर स्वीकार किया कि पुलिस ने उसे वारंट की जानकारी दी थी। पुलिस रिपोर्ट और आरोपी के बयान में इस स्पष्ट विरोधाभास को कोर्ट ने गंभीर माना।

हाईकोर्ट की तीखी टिप्पणी

हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि अपराधी स्थानीय पुलिस को 'मैनेज' कर रहा था और जानबूझकर गैर-जमानती वारंट को निष्प्रभावी किया गया, ताकि मामले की मेरिट पर सुनवाई न हो सके। कोर्ट ने इसे सेवा में कदाचार, अक्षमता और अवमानना की श्रेणी में आने वाला आचरण बताया। खंडपीठ ने वारंट की तामील से जुड़े सभी संबंधित पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे हलफनामा दाखिल कर अपनी विफलता का स्पष्ट कारण बताएं।

अवध विश्वविद्यालय: शिक्षकों ने प्रशासन को दिया 72 घंटे का अल्टीमेटम

प्राचार्य व कर्मचारियों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने और एसडीएम से सार्वजनिक माफी की मांग

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या। डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय एक बार फिर प्रशासनिक हस्तक्षेप और शैक्षणिक स्वायत्तता की लड़ाई का अखाड़ा बनता नजर आ रहा है। अंबेडकर नगर के बीएनकेवी महाविद्यालय में परीक्षा के दौरान एसडीएम की कथित मनमानी कार्रवाई के विरोध में शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने जिला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।

संयुक्त शिक्षक मोर्चा के अध्यक्ष डॉ. जन्मजय तिवारी ने प्रशासन पर विश्वविद्यालयीय व्यवस्था में सीधा दखल देने का आरोप लगाते हुए कहा कि 2 फरवरी को हुई कार्रवाई पूरी तरह असंवैधानिक और तानाशाही रवैये का प्रतीक है। उन्होंने प्राचार्य व कर्मचारियों पर दर्ज मुकदमों को तत्काल वापस लेने और एसडीएम से सार्वजनिक माफी की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी कि यदि 72 घंटे के भीतर मांगें नहीं मानी गईं, तो अवध विश्वविद्यालय से संबद्ध सातों जिलों के महाविद्यालयों के शिक्षक सामूहिक बहिष्कार कर व्यापक आंदोलन छेड़ेंगे।

वहीं आक्टा के महामंत्री प्रो. अमोल कुमार सिंह ने कहा कि परीक्षा संचालन पूरी तरह विश्वविद्यालय के नियंत्रण में होता है और इसके लिए पहले ही स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती का पत्र जारी किया जा चुका था। इसके बावजूद जिला प्रशासन द्वारा विश्वविद्यालय को विश्वास में लिए बिना की गई कार्रवाई न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि शैक्षणिक गरिमा पर सीधा हमला भी है।

शिक्षक नेताओं ने पुलिस बल द्वारा हथियारों के साथ परीक्षा कक्षों में प्रवेश कर छात्रों की तलाशी को शर्मनाक और भय पैदा करने वाला कदम बताया। उनका कहना है कि शिक्षा के मंदिर में डर और दबाव का माहौल बनाकर प्रशासन ने अपनी असंवेदनशीलता उजागर कर दी है। अब यह टकराव सिर्फ एक परीक्षा केंद्र तक सीमित नहीं रहा, बल्कि विश्वविद्यालय बनाम प्रशासन की लड़ाई में बदल चुका है। आने वाले 72 घंटे तय करेंगे कि यह मामला बातचीत से सुलझेगा या अवध विश्वविद्यालय एक बड़े शैक्षिक आंदोलन का केंद्र बनेगा।

होलिका दहन स्थल पर बनेगा पार्क, लगेगी बाबा साहब की प्रतिमा

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या। 'नगर की सरकार आपके द्वार' अभियान के तहत महापौर गिरीश पति त्रिपाठी एवं नगर आयुक्त जयेंद्र कुमार ने अमानीगंज वार्ड का जायजा लिया। इस दौरान होलिका दहन स्थल पर पार्क निर्माण, झूला-स्लाइड लगाने एवं बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करने पर सहमति बनी। प्रधानमंत्री आवास, नाली जोड़ने, सफाई, टूटी पटिया, जलभराव, बिजली खंभा और पेयजल समस्या को लेकर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। वार्ड में बंद शौचालयों पर भी कार्रवाई के आदेश दिए गए। इस दौरान पेयजल की जांच में पानी शुद्ध पाया गया। टीडीएस 450 रहा और क्लोरीन भी मौजूद मिला। फागिंग कार्य पर भी संतोष जताया गया।

प्रवक्ता की नियुक्ति पर फिर उठे सवाल, जांच शुरू

डीआईओएस कार्यालय पर लटकी कार्रवाई की तलवार

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या। जनपद के श्रीअनंत इंटर कॉलेज, खपराडीह में प्रवक्ता वीरेंद्र बहादुर सिंह की नियुक्ति में कथित फर्जीवाड़े का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। लंबे समय से विवादों में रही इस नियुक्ति की जांच अब प्रदेश शासन के निर्देश पर दोबारा शुरू कर दी गई है।

विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन कृष्ण कुमार गुप्ता ने इस प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए त्रिस्तरीय जांच समिति का गठन किया है। इस समिति में अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) प्रयागराज को सदस्य नामित किया गया है और उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि मामले की निष्पक्ष जांच कर विस्तृत रिपोर्ट शासन को सौंपें।

जांच समिति को निर्देशित किया गया है कि वह प्रवक्ता वीरेंद्र बहादुर सिंह की नियुक्ति की वैधता फर्जी अधियापन के आरोप, नियुक्ति प्रक्रिया में कूटरचना, डीआईओएस कार्यालय की भूमिका सहित सभी बिंदुओं पर गहन जांच करे। साथ ही, नियुक्ति से संबंधित सभी अभिलेख रिपोर्ट के साथ शासन को पेश किया जाए। बताया जा रहा है कि पूर्व में भी इस नियुक्ति को लेकर सवाल उठे थे, लेकिन उस समय मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था।

रामनगरी में भी 'घूसखोर पंडत' पर सियासी बवाल

पूर्व मंत्री पवन पांडेय की सड़कों तक उतरने की चेतावनी

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या। नेटफ्लिक्स पर प्रस्तावित वेब सीरीज़ 'घूसखोर पंडत' उत्तर प्रदेश में विवादों के केंद्र में आ गई है। रिलीज से पहले ही इस सीरीज़ ने ऐसा तूफ़ान खड़ा कर दिया है,

जिसने राजनीति, समाज और प्रशासन—तीनों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे ने शुक्रवार शाम इस वेब सीरीज़ के नाम और कथानक पर कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए इसे समाज को बांटने वाली साजिश करार दिया।

उन्होंने कहा कि पंडत जैसे सम्मानित शब्द को घूसखोरी से जोड़ना केवल एक वर्ग नहीं, बल्कि पूरे समाज की भावनाओं पर चोट है। पवन पांडे ने आरोप लगाया कि वेब सीरीज़ के जरिए एक विशेष समाज को जानबूझकर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। सपा नेता ने सरकार और नेटफ्लिक्स प्रबंधन से दो टूक मांग की है या तो सीरीज़ का नाम तुरंत बदला जाए या फिर इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। यदि जल्द निर्णय नहीं हुआ तो सड़क पर आंदोलन होगा।

ओमान वार्ता के तुरंत बाद 14 जहाज, 15 कंपनियां और 2 व्यक्ति अमेरिकी निशाने पर

ईरान पर अमेरिका का नया प्रतिबंध प्रहार, तेल कारोबार पर कसा शिकंजा

- ओमान में अप्रत्यक्ष परमाणु वार्ता के तुरंत बाद अमेरिका का बड़ा कदम
- ईरान से जुड़े 14 जहाज, 15 कंपनियां और 2 व्यक्ति प्रतिबंध सूची में
- तुर्किये, भारत और श्व के झंडे वाले जहाज भी निशाने पर
- अमेरिकी विदेश मंत्रालय का दावा–तेल आय से फैलती है क्षेत्रीय अस्थिरता
- ट्रंप की 'अधिकतम दबाव' नीति पर कोई ढील नहीं
- ईरान ने वार्ता को बताया सकारात्मक, लेकिन प्रतिबंधों से बढ़ा तनाव
- अमेरिका की दोहरी रणनीति- संवाद भी, दबाव भी

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

नई दिल्ली। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर ओमान की राजधानी मस्कट में अमेरिका और ईरान के बीच हुई अप्रत्यक्ष बातचीत समाप्त होते ही वॉशिंगटन ने तेहरान के खिलाफ नए प्रतिबंधों का ऐलान कर दिया। इन ताज़ा प्रतिबंधों के तहत ईरान के तेल और पेट्रोकेमिकल निर्यात से जुड़े 14 जहाजों, 15 कंपनियों और 2 व्यक्तियों को अमेरिकी प्रतिबंध सूची में शामिल किया गया है।

अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इन प्रतिबंधों का उद्देश्य ईरान की उस आय को रोकना है, जिसका इस्तेमाल वह क्षेत्रीय अस्थिरता फैलाने और आंतरिक दमनात्मक कार्रवाइयों में करता है। मंत्रालय के प्रवक्ता टॉमी पिगॉट ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 'अधिकतम दबाव' नीति पूरी सख्ती से लागू है और ईरान के अवैध तेल कारोबार को लेकर किसी तरह की नरमी नहीं बरती जाएगी।

नए प्रतिबंधों के दायरे में जिन 14 जहाजों को शामिल किया गया है, उन पर ईरानी तेल की ढुलाई का आरोप है। इनमें तुर्किये, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के झंडे वाले पोत भी शामिल बताए गए हैं। इसके अलावा जिन 15 कंपनियों और 2 व्यक्तियों पर कार्रवाई हुई है, उनके साथ अमेरिका के अधिकार क्षेत्र में आने वाले किसी भी व्यक्ति या संस्था का लेन-देन अब गैरकानूनी माना जाएगा। गौरतलब है कि अमेरिका पहले भी कई बार ईरान के तेल निर्यात को सीमित करने के लिए ऐसे प्रतिबंध लगा चुका है। ट्रंप के पहले कार्यकाल से ही वॉशिंगटन की नीति रही है कि वैश्विक स्तर पर ईरानी तेल की खरीद को हतोत्साहित कर उसकी अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ाया जाए, ताकि वह अपने परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय गतिविधियों पर रुख बदलने को मजबूर हो।

दिलचस्प पहलू यह है कि प्रतिबंधों की घोषणा ऐसे समय पर हुई है, जब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने ओमान में हुई अप्रत्यक्ष वार्ता को सकारात्मक और रचनात्मक बताया था। हालांकि, अमेरिकी फैसले से यह संकेत भी मिलता है कि वॉशिंगटन कूटनीतिक संवाद के साथ-साथ आर्थिक दबाव की रणनीति पर भी समानांतर रूप से आगे बढ़ रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका दोहरी रणनीति अपना रहा है–एक ओर बातचीत के जरिए समाधान की कोशिश, तो दूसरी ओर प्रतिबंधों और सैन्य दबाव के माध्यम से ईरान को झुकाने का प्रयास। पश्चिम एशिया में बढ़ती अमेरिकी सैन्य मौजूदगी और सख्त बयानों ने पहले ही क्षेत्रीय तनाव को ऊंचा कर रखा है।

लखनऊ में राहुल गांधी के खिलाफ लगी होर्डिंग

स्वराज इंडिया ब्यूरो

लखनऊ। राजधानी लखनऊ में कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ लगाए गए एक होर्डिंग ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। यह होर्डिंग उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और भाजपा नेता दिनेश प्रताप सिंह के आवास के बाहर लगाए जाने की बात सामने आई है। होर्डिंग में राहुल गांधी को लेकर तीखे और आपत्तिजनक राजनीतिक संदेश लिखे होने का दावा किया जा रहा है।

जानकारी के अनुसार, होर्डिंग में राहुल गांधी पर सीधे तौर पर सवाल उठाते हुए उन्हें निशाने पर लिया गया है। जैसे ही यह मामला सामने आया, कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं में नाराजगी फैल गई। कांग्रेस का आरोप है कि सत्ताधारी दल के मंत्री के आवास के बाहर इस तरह का होर्डिंग लगना राजनीतिक मर्यादाओं का उल्लंघन है और इससे माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यह पूरा मामला सुनियोजित राजनीतिक हमला है और इसका उद्देश्य जनता का ध्यान असली मुद्दों से भटकाना है। उन्होंने प्रशासन से होर्डिंग हटाने और जिम्मेदार लोगों

- मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के आवास के बाहर लगाई गई होर्डिंग, सियासी विवाद शुरू

के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध दर्ज कराने की तैयारी भी शुरू कर दी है।

वहीं, भाजपा की ओर से इस मामले पर फिलहाल कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। हालांकि, पार्टी से जुड़े कुछ लोगों का कहना है कि यह राहुल गांधी के हालिया बयानों के जवाब में की गई राजनीतिक प्रतिक्रिया है। प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक, होर्डिंग लगाए जाने की अनुमति और नियमों के उल्लंघन को लेकर जांच की जा रही है। नगर निगम और पुलिस को मामले की जानकारी दे दी गई है और यह देखा जा रहा है कि होर्डिंग किसने और किन शर्तों पर लगवाया।

हरदोई में मौत बनकर दौड़ा डंपर भाई-बहन और मौसी को कुचला

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

हरदोई। सुरसा थाना क्षेत्र में शनिवार को सड़क नहीं, मौत दौड़ती दिखी। बेकाबू रफ्तार में भागते डंपर ने सामने से आ रही बाइक को इस कदर रौंद दिया कि भाई-बहन और उनकी मौसी की मौके पर ही तड़प-तड़प कर मौत हो गई। टक्कर इतनी खौफनाक थी कि तीनों उछलकर सड़क पर गिर पड़े, शव बिखर गए और पूरा घटनास्थल किसी वीभत्स अपराध-स्थल में तब्दील हो गया।

मृतकों की पहचान मधु अवस्थी (23), उनके भाई आदर्श (20) और मौसी कामिनी के रूप में हुई है। आदर्श अपनी बहन को सीटीईटी परीक्षा दिलाने जा रहा था। परिवार में परीक्षा की तैयारी चल रही थी, लेकिन किसे पता था कि यह सफर जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा। मौसी भी रास्ते में घर छोड़ने की बात कहकर बाइक पर बैठ गई थीं। कुछ ही मिनटों बाद तीनों की सांसें थम चुकी थीं।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार डंपर पलक झपकते ही बाइक पर चढ़ गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार करीब पांच फीट तक हवा में उछलकर सड़क पर जा गिरे। सिर में गंभीर चोट लगने से तीनों ने मौके पर

- बाइक सवार 5 फीट तक हवा में उछलकर सड़क पर गिरे, हादसे के बाद फरार हुआ ड्राइवर

ही दम तोड़ दिया। आदर्श हेलमेट पहने हुए था, फिर भी उसकी जान नहीं बच सकी–यह रफ्तार और लापरवाही की हैवानियत को उजागर करता है।

हद तो तब हो गई जब डंपर बाइक को फंसाए हुए कुछ दूरी तक घसीटता चला गया। इसके बाद चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। यह केवल हादसा नहीं, बल्कि सड़क पर खुला अपराध बताया जा रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और डंपर को

- सड़क पर मौत बनकर दौड़ा डंपर
- भाई-बहन और मौसी को कुचलकर ड्राइवर फरार
- CTET परीक्षा देने जा रही युवती की दर्दनाक मौत
- टक्कर इतनी तेज कि शव सड़क पर बिखर गए
- हेलमेट के बावजूद नहीं बची युवक की जान
- बाइक डंपर में फंसकर काफी दूर तक घिसटी
- इलाके में आक्रोश, प्रशासन पर गंभीर सवाल

जब्त कर लिया है। फरार चालक की तलाश जारी है।

एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत से गांव में कोहराम मचा हुआ है। लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस मार्ग पर भारी वाहन बेलगाम रफ्तार से दौड़ते हैं और प्रशासन आंख मूंदे बैठा रहता है। सवाल यह है कि आखिर कब तक सड़कें यूं ही लहू से रंगी जाती रहेंगी?

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक **सपना देवी** द्वारा हर्षिता प्रिंटर्स 127/875, साकेत नगर, कानपुर नगर- (उप्र) से मुद्रित व 119/13, दर्शनपुरवा, कानपुर नगर- 208012 (उप्र) से प्रकाशित। **संपादक: अनूप कुमार** **RNI No.:** UPHIN/2023/86769 ❍ **Email:** swarajindia2023@gmail.com ❍ Mob: 7800009853, ❍ **Website:** www.swarajindianews.com ❍ (समस्त वाद-विवाद कानपुर न्यायालय के अधीन होंगे) **प्रधान संपादक: पुरुषोत्तम द्विवेदी**

ई-पेपर पढ़ने के लिए क्लिक करें
https://epaper.swarajindianews.com